सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 04, नई दिल्ली । रविवार, 17 मार्च 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते।

03 दिल्ली की सभी सात सीटों पर इस दिन होगा चुनाव
06 डर कर काम करता है सरकारी तंत्र
08 केजरीवाल को बड़ी राहत, 15 हजार निजी मुचलके पर मिली जमानत

एलजी वीके सक्सेना ने दूर की दिल्ली की सबसे बाधा

जाम से मिलेगी मुक्ति, लोगों को आवाजाही में होगी आसानी

दिल्ली के रिंग रोड पर मजनू का टीला गुरुद्वारा पर लग रहे भयंकर जाम से जनता को राहत मिल सकेगी। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने गुरुद्वारा मजनू का टीला क्रॉसिंग के सामने डीडीए की जमीन पर फुटओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे एफओबी के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। यह निर्माण डीडीए की 123 एकड़ जमीन पर होना है।

संजय बाटला

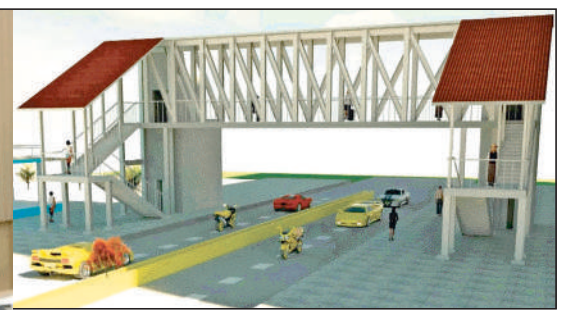

नई दिल्ली। रिंग रोड पर मजनू का टीला गुरुद्वारा पर लग रहे भयंकर जाम से जनता को राहत मिलने की उम्मीद जग गई है। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने गुरुद्वारा मजनू का टीला क्रॉसिंग के सामने डीडीए की जमीन पर फुटओवर ब्रिज (एफओबी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

इससे एफओबी के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अब आठ माह से लटके एफओबी के निर्माण हो जाने के बाद इस स्थान पर लंबे समय से जारी यातायात की सुलभ होगा और क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।जिस जमीन पर निर्माण होना है वह डीडीए की 123 एकड़ जमीन का हिस्सा है।

योजना के अनुसार गुरुद्वारा के सामने पीडब्ल्यूडी रोड पर एफओबी को इस तरह से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जब भी इस जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए तो इसे आसानी से तोड़ा व स्थानांतरित किया जा सके।

निर्माण की अनुमति के लिए डीडीए से अनुरोध

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस स्थान पर प्रस्तावित एफओबी के पूर्वी छोर पर डीडीए की जमीन पर फुटिंग, सीढ़ी और लिफ्ट के निर्माण की अनुमति के लिए डीडीए से अनुरोध किया था। जिसके बाद यह मामला डीडीए मुख्यालय से होता हुआ एलजी के पास पहुंचा था। जिस पर एलजी ने अनुमति दे दी है।

जाम दूर करने की योजना

बता दें कि मध्य और उत्तरी दिल्ली के बीच बाहरी रिंग रोड से चलने वाले लोगों को मजनू का टीला गुरुद्वारा के सामने जाम दूर करने की योजना को आठ माह पहले उस समय झटका लगा था। जब पीडब्ल्यूडी द्वारा योजना पर शुरू किए गए काम को डीडीए ने रुकवा दिया था।

फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए काम शुरू

योजना के तहत मजनू का टीला गुरुद्वारा के सामने फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाया जाना है, इसके अलावा एक स्लिप रोड बनाया जाना है। फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया था, जिसे डीडीए ने यह कहकर रुकवा दिया था कि निर्माण उनकी जमीन पर हो रहा था।यह काम उसी समय से बंद पड़ा है।

77 कॉरिडोर को जाम से राहत दिलाने की योजना

विभाग ने 77 कॉरिडोर को जाम से राहत दिलाने की योजना के तहत दिशा-निर्देश के मद्देनजर इस स्थान पर एक एफओबी का निर्माण करने की योजना बनाई है। इस जंक्शन पर यातायात को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2020 को एफओबी बनाने के निर्देश दिए गए थे। इस एफओबी के पूर्वी छोर (सीढ़ी और लिफ्ट) का निर्माण पीडब्ल्यूडी के मौजूदा नाले के ठीक पास किया जाना है।

पीडब्ल्यूडी दो बार डीडीए से अनुरोध कर कह चुका

पीडब्ल्यूडी ने डीडीए मुख्यालय को लिखे अपने पत्र में कहा कि डीडीए अधिकारियों ने यह कहते हुए साइट पर काम रोक दिया है कि यह जमीन डीडीए की है। पीडब्ल्यूडी दो बार डीडीए से अनुरोध कर कह चुका है कि यदि भूमि उसकी है तो जनहित में इस स्थान पर सीढ़ी और लिफ्ट के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति जारी की जाए।मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई।

डीडीए से योजना के लिए जमीन देने के लिए कहा

मामला जब एलजी के संज्ञान में आया तो उन्होंने डीडीए से योजना के लिए जमीन देने के लिए कहा। इसके बाद इस मामले की फाइल चलाई गई, डीडीए और पीडब्ल्यूडी ने संयुक्त रूप से मौके का मुआयना किया, डीडीए ने रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजी।

गुरुद्वारा के सामने ही स्लिप रोड बनाया

योजना के दूसरे चरण में मजनू का टीला गुरुद्वारा के सामने ही स्लिप रोड बनाया जाना है ताकि रिंग रोड पर वजीराबाद की ओर से कश्मीरी गेट की ओर आने वाले वाहन इस स्लिप रोड का इस्तेमाल कर बगैर किसी अवरोध के सीधे निकल सकें। जिन लोगों को इस प्वाइंट पर लालबत्ती हटाने के बाद यूटर्न से दाहिनी ओर जाना है वही मुख्य मार्ग पर आएं।इस स्लिप रोड को उसी तरह बनाया जाना है जिस तरह चंदगीराम अखाड़ा के पास बनाया गया है।

दिल्ली में रविवार को 'रन फॉर गुड हैपनिंग' मैराथन, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जवाहर लाल नेहरू (JLN) स्टेडियम में होने वाले मैराथन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों के मुताबिक, रविवार को JLN स्टेडियम में 'रन फॉर गुड हैपनिंग' मैराथन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से लगभग 2,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि रविवार सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक भीष्म पितामह मार्ग, कोटला रेड लाइट, लोधी रोड, जोर बाग रोड, दयाल सिंह/सीजीओ रोड आदि पर यातायात व्यवस्था को जरूरत के मुताबिक कंट्रोल या डायवर्ट किया जाएगा।

यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि वे सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें। आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाने वालों को अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए।

एडवाइजरी में कहा गया है कि, ₹यात्रियों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।

दिल्ली में जून तक बढ़ी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020, केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि ईवी नीति को जून 2024 तक विस्तारित कर हम पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को मजबूती दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में हम दिल्ली को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक जनवरी 2024 के बाद खरीदा गया कोई भी वाहन इस विस्तार के तहत लाभ के लिए पात्र होगा।

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने मौजूदा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अग्रली 30 जून तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मौजूदा नीति के तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन इस विस्तार अवधि में भी जारी रहेंगे। एक जनवरी 2024 के बाद खरीदा गया कोई भी वाहन इस विस्तार के तहत लाभ के लिए पात्र होगा।

नई नीति पर काम कर रही सरकार

फिलहाल, दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 पर काम कर रही है और विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली ईवी नीति को जून 2024 तक विस्तारित कर हम राजधानी में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को मजबूती दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में हम दिल्ली को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति सात अगस्त 2020 को तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचित की गई थी, जिसे बाद में 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार अब ईवी नीति 2.0 तैयार करने की प्रक्रिया में है।

दिल्ली में बढ़े इलेक्ट्रिक वाहन

24 मई 2023 को आयोजित एक परामर्श में ओईएम, व्यवसायों और सरकारी विभागों के साथ-साथ आम जनता सहित प्रमुख हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। अगस्त 2020 में लॉन्च होने के बाद से दिल्ली में ईवी अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। नीति लॉन्च के बाद से दिल्ली में 1,80,000 से अधिक ईवी पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें मुख्य रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहन शामिल हैं।

दिल्ली में औसत वार्षिक ईवी खरीद 2020 में 3 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2023 तक 12 प्रतिशत हो गया है। दिसंबर 2023 में दिल्ली में ईवी खरीद 16 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक मासिक ईवी खरीद है। मौजूदा ईवी नीति के तहत सरकार ने विभिन्न ई-वाहन खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर कुल 179 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया है।

सरकार ने अब तक कितना दिया प्रोत्साहन

सरकार द्वारा दो पहिया ई-वाहनों के लिए 64 करोड़ रुपये और तिपहिया ई-वाहनों के लिए 100 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन प्रदान किया जा चुकी है। दिल्ली में ईवी खरीद में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण दिल्ली में जगह-जगह चार्जिंग प्वाइंट्स और स्वैपिंग स्टेशन का होना है। दिल्ली सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए पूरी दिल्ली में 4500 सार्वजनिक चार्जिंग प्वाइंट और 1,600 निजी चार्जिंग प्वाइंट लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बैटरी स्वैपिंग में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, फिलहाल दिल्ली में लगभग 318 स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।

वैष्णो देवी-नई दिल्ली वंदे भारत का बदला समय

कटड़ा से इतने बजे चला करेगी अब वंदे भारत ट्रेन

परिवहन विशेष न्यूज

श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस (22440) के समय में 18 मार्च से बदलाव किया जा रहा है। कटड़ा से अपराह्न तीन बजे के स्थान अपराह्न 255 बजे प्रस्थान चलेगी। जम्मू तवी में यह शाम 413 बजे के स्थान पर 408 बजे पहुंचेगी। जम्मू तवी से नई दिल्ली के बीच यह पुराने समय के अनुसार चलेगी।

नई दिल्ली। श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस (22440) के समय में 18 मार्च से बदलाव किया जा रहा है। कटड़ा से अपराह्न तीन बजे के स्थान अपराह्न 2:55 बजे प्रस्थान चलेगी। जम्मू तवी में यह शाम 4:13 बजे के स्थान पर 4:08 बजे पहुंचेगी। जम्मू तवी से नई दिल्ली के बीच यह पुराने समय के अनुसार चलेगी।

दिल्ली से सूबेदारगंज, मालदा टाउन, पुरी और मुंबई सेंट्रल के लिए चलेगी विशेष ट्रेन

होली के अवसर पर घर जाने वालों को ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। लगभग सभी रूट की ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची है। यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए होली विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। दिल्ली से सूबेदारगंज, मालदा टाउन, पुरी और मुंबई सेंट्रल के लिए होली विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इन सभी ट्रेनों में सामान्य, शयनयान व वातानुकूलित श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे।

सूबेदारगंज-आनंद विहार टर्मिनल विशेष (04145)

सूबेदारगंज से विशेष ट्रेन 20 से 24 मार्च, 26 से 29 मार्च और 31 मार्च को रात साढ़े नौ बजे रवाना होगी। आनंद विहार टर्मिनल से यह विशेष ट्रेन 21 से 25 मार्च, 27 से 30 मार्च और एक अप्रैल को सुबह साढ़े नौ बजे चलेगी। रास्ते में इसका ठहराव फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टुंडला और अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर होगा।

मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनल विशेष (03435/03436)

मालदा टाउन से 25 मार्च से एक अप्रैल तक सुबह साढ़े नौ बजे चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल से 26 मार्च से दो अप्रैल तक शाम सात बजे प्रस्थान करेगी। रास्ते में न्यू फरक्का, बड़हरवा, साहिबगंज, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, अभयपुर, क्यूल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, पंडीत दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, गोविंदपुरी स्टेशनों पर रुकेगी।

पुरी-हजरत निजामुद्दीन विशेष (08475/08476)

पुरी से यह विशेष ट्रेन 22 से 29 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 4.50 बजे चलेगी। हजरत निजामुद्दीन से 23 से 30 मार्च तक प्रत्येक शनिवार को रात 11.35 बचे रवाना होगी। रास्ते में इसका ठहराव खोरधा रोड, भुवनेश्वर, नराजमर्थापुर, ढेंकनाल, अंगुल, रेढ़ाखोल, संबलपुर सिटी, झारसुगोड़ा रोड, बिलासपुर, न्यू कटनी, बीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, आगरा छावनी और मथुरा रेलवे स्टेशन पर होगा।

मुंबई सेंट्रल-सराय रोहिल्ला विशेष (09003/09004)

यह विशेष ट्रेन 22 से 29 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार को शाम चार बजे मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी। दिल्ली सराय रोहिल्ला से यह 23 से 30 मार्च तक प्रत्येक शनिवार को शाम 5.25 बजे चलेगी। रास्ते में इसका ठहराव बोरीवली, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, आबू रोड, मारवाड़, अजमेर, फुलेरा, रींगस, रेवाड़ी, गुड़गांव, दिल्ली छावनी रेलवे स्टेशन पर होगी।

महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ ने बनाई नई नीति

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक नया कदम उठाया है। सोमवार को डब्ल्यूएचओ ने कहा कि महिलाओं की बढ़ती कमजोरियों पर ध्यान देने और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में स्वास्थ्य पेशेवरों के पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को एकीकृत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ साझेदारी करेगा। यह अभियान 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस(Human Rights Day) तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है जिनके लिए हिंसा की स्थिति में स्वास्थ्य देखभाल हमेशा पहला कार्य होगी।

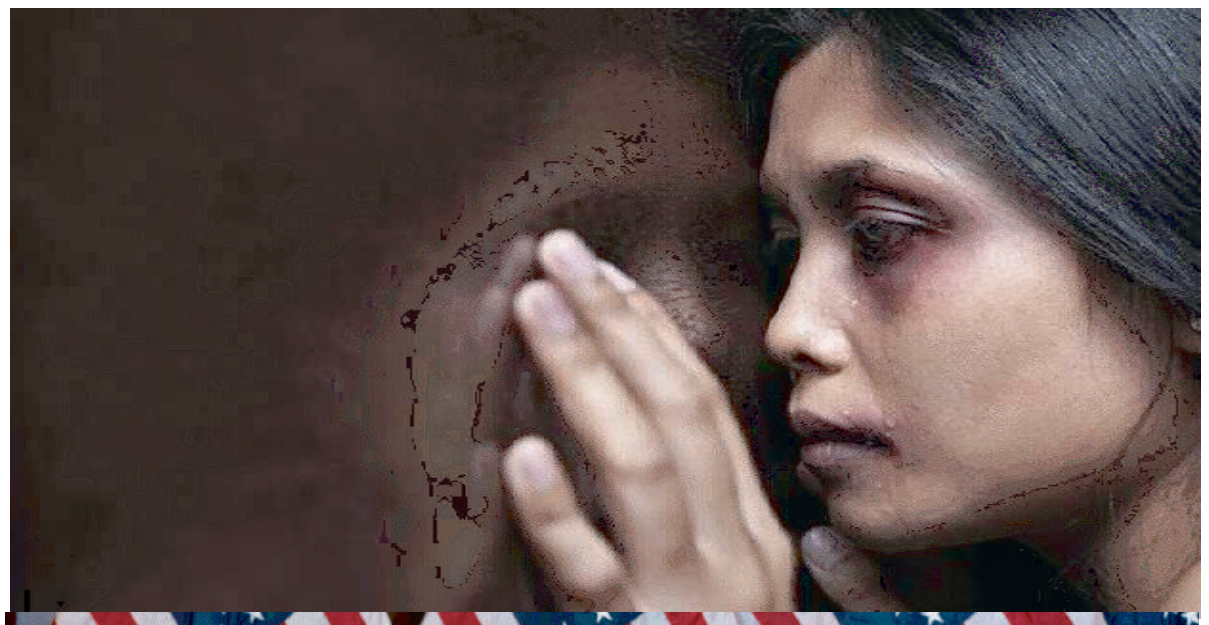

विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की निवर्तमान क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र एक बहुक्षेत्रीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और लड़कियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की अधिक संभावना है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अक्सर महिलाओं के लिए पेशेवर संपर्क के लिए पहली प्रायोरिटी होते हैं। तीसरा सारी महिलाएं अपने जीवन में किसी न किसी समय स्वास्थ्य सेवाएं लेने की संभावना रखती हैं। अंत में स्वास्थ्य प्रणालियों की डब्ल्यूएचओ की वैश्विक कार्ययोजना के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने का आदेश दिया गया है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों की मानें तो दुनियाभर में तीन में से लगभग एक महिला अपने जीवन में शारीरिक या फिर यौन हिंसा से जूझती हैं और इनमें से ज्यादातर मामले इंटीमेट पार्टनर की हिंसा के रुप में होते हैं या आसान शब्दों कहें तो महिलाओं को उन लोगों से सबसे ज्यादा खतरा होता है जिनके साथ वे रहती हैं। अनुमान बताते हैं कि दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र इस मामले में लगभग 33 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

यूएन एजेंसी ने बनाई नई नीति

जैसे-जैसे महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ती हैं संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने अतंरग साथी और यौन हिंसा को होने से पहले रोकने के लिए नीति मार्गदर्शन विकसित किया है। इस नीती का नाम महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना है।

महिलाओं के लिए बनाई गई Respect नामक नीति

आपको बता दें कि महिलाओं के लिए बनाई गई नई नीति रिस्पेक्ट(Respect) सात रोकथाम रणनीतियों का संक्षिप्त रुप है जो व्यक्तिगत, घरेलू, समुदाय और समाज के स्तर पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जोखिम कारकों को कम करने और सुरक्षात्मक कारकों को बढ़ाने का प्रयास करती है। इस अभियान के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी भाग्यदारी की घोषणा की है। भारत के साथ-साथ सदस्य देशों में महिलाएं के लिए Respect कार्यक्रम के अंतर्गत अलग-अलग ट्रेनिंग रखी जाएंगी और उन्हें इससे बचाने के लिए वर्कशॉप्स भी आयोजित की जाएंगी।

इन कारणों से बच्चों में होती है Calcium की कमी, Parents जानें बचाव के तरीके

बढ़ते बच्चों और टीनएजर की अच्छी सेहत के लिए जरुरी है कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी न हो। पर्याप्त कैल्शियम उनकी हड्डियों को जीवनभर टूटने से बचाता है और उन्हें जीवन में आगे चलकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्या नहीं होती। यदि आप भी चाहते हैं कि बच्चों को जीवन भर हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारियां न हो तो आप उनके डाइट में कैल्शियम और विटामिन-डी वाले आहार को शामिल करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि बच्चों को कितनी मात्रा में कैल्शियम की जरुरत होती है....

कितनी कैल्शियम की मात्रा जरुरी ?

एक्सपर्ट्स की मानें तो बच्चों की बेहतर ग्रोथ के लिए जरुरी है कि 1 से 3 साल के बच्चों की रोजाना करीब 700 मिलीग्राम कैल्शियम की आपूर्ति हो। जबकि 4-8 साल के बच्चों को 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जरुरत होती है। वहीं 9 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को 1300 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम की जरुरत होती है।

क्यों होती है कैल्शियम की कमी ?

. यदि बच्चे ने 1 साल से कम उम्र तक मां का दूध न पीया हो।

. विटामिन-डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी होती है।

. कुछ हार्मोन जैसे शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह बनते हैं।

. पैराथायराइड ग्लैंड के कम विकसित होने से यह समस्या हो सकती है।

. जन्म देते समय यदि मां को डायबिटीज हो तो बच्चे में कैल्शियम की कमी हो सकती है।

. जिजॉर्ज सिंड्रोम नाम के जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण बच्चों में कैल्शियम की कमी हो सकती है।

कैसे करें पूरी ?

. बच्चों के शरीर में से कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए उन्हें दूध से बनी चीजें दें। इसके अलावा सोया से बनी चीजें, फिश बोन, बादाम, स्वीट पौटेटो, तरह-तरह की दालें, बीन्स, ब्रोकली, हरी मटर को शामिल करें।

. बच्चों को रोजाना 15 मिनट सुबह और शाम को धूप जरुर दिलवाएं।

. डॉक्टर की सलाह पर उन्हें विटामिन-डी और कैल्शियम सीरप दें।

वक्त पर पकड़ना है काला मोतिया तो एक बार करें ये काम, पॉल्यूशन का जंजाल होगा खत्म

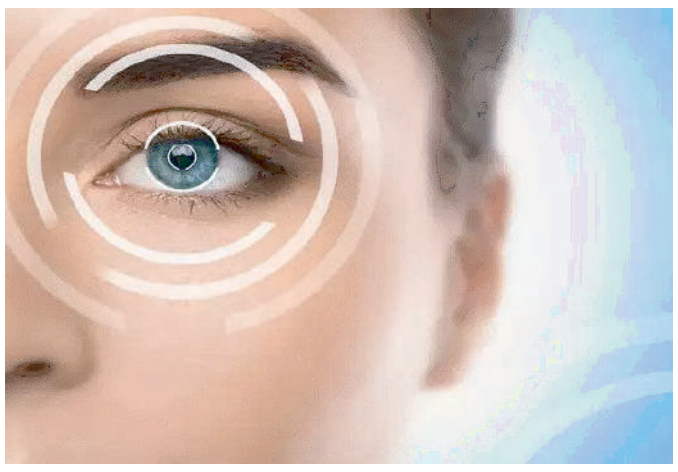

पॉल्यूशन के कारण लोगों को आंखों में जलन, एलर्जी और गले में खराश जैसी परेशानियां हो रही हैं। इससे बचने के लिए विशेष टिप्स दिए गए हैं। आंखों की जांच और डाइलेट करने से आंखों की परेशानियों को समझना आसान होता है। मोबाइल का अधिक इस्तेमाल मायोपिया को बढ़ावा देता है।

पॉल्यूशन ने अपना जोर लगाया हुआ है। लोगों को इस वजह से आंखों में जलन, सांसों की परेशानी, एलर्जी की शिकायत, गले में खराश समेत तमाम तरह की परेशानियों ने घेर रखा है। साथ ही मौसम बदल रहा है और त्योहारों का सीजन भी चल रहा है।

ऐसे में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं सेहतमंद बने रहने के लिए बेस्ट टिप्स। इन्हें अपनाकर आप खुद को अच्छी सेहत का तोहफा दे सकते हैं।

1. साल में एक बार आई चेकअप

साल में एक बार आंखों की जांच होनी चाहिए, वह भी आंखों को डाइलेट करके। आजकल कंप्यूटर के माध्यम से टेस्टिंग होती है। लेकिन आंखों की अंदरूनी परेशानी का पता लगाने के लिए डाइलेट करने के खास लिक्विड (Tropicamide, Phenylephrine Hydrochloride) की चंद बूंदें आंखों में डाली जाती हैं।

इससे डॉक्टर को आंखों के भीतरी हिस्से, नसें आदि अच्छी तरह दिख जाती हैं। इससे आंखों की परेशानियों को समझना आसान हो जाता है। इस जांच का चलन ज्यादातर शुगर पेशेंट्स और उम्र से जुड़ी परेशानियों में होता है।

फिर भी इस तरह की जांच सभी के लिए होनी चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद हर साल आंखों का प्रेशर जरूर चेक कराएं। इससे काला मोतिया वक्त पर पकड़ में आ जाता है।

2. मोबाइल से दूरी

मोबाइल की जरूरत सभी को है। काफी संख्या में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनकी यह जरूरत लत बन गई है। लेकिन 6 से 13 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। इससे मायोपिया हो रहा है।

इसमें दूर की निगाह कमजोर हो जाती है। किसी शख्स को 6 फुट की दूरी पर मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट साफ दिखाई न दे तो इसका मतलब है कि वह मायोपिया का शिकार हो सकता है।

ज्यादातर बच्चे मायोपिया वाले ही होते हैं। आम रुटीन में हम एक मिनट में 20 से 25 बार पलकों को झपकाते हैं, लेकिन स्क्रीन देखते समय यह महज 5 से 7 बार रह जाती है।

3. 20:20:20 फॉर्मूला

अगर कोई शख्स किसी से बात कर रहा हो, कहीं जा रहा हो तो वह स्वाभाविक तौर पर कभी नजदीक तो कभी दूर देखता रहता है। लगातार नजदीक देखने का मसला नहीं बनता। लेकिन जब कोई शख्स लगातार मोबाइल या लैपटॉप आदि की स्क्रीन को देखता रहता है तो 'दूरदर्शन' की जरूरत होती है। इसलिए ऐसे शख्स को 20:20:20 फॉर्मूले पर अमल करना जरूरी है यानी हर 20 मिनट बाद 20 बार पलकें झपकना, फिर लगातार 20 सेकंड तक 20 फुट या इससे दूर देखना चाहिए।

इससे आंखों को आराम मिलता है। साथ ही ड्राई आंखों की परेशानी भी कम होती है। इसके अलावा स्क्रीन पर काम करते हुए बार-बार पलकें झपकाएं। याद रखें, हर 5 सेकंड में एक बार पलकें झपकनी चाहिए।

क्या रात में नहीं सोते आपके बच्चे तो पैरेंट्स अपनाएं ये तरीके

बच्चों के स्वास्थ्य का यदि ध्यान न रखा जाए तो वह बीमार हो जाते हैं। बच्चे हो या बड़े सभी के स्वस्थ शरीर के लिए नींद पूरी होना जरुरी है। ऐसे में यदि आपका बच्चा भी अच्छे से नहीं सोना या बिना नींद पूरे किए उठ जाते हैं तो इसका खराब असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कई पेरेंट्स इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा रात में अच्छी तरह से नहीं सोता और चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में आपकी यह परेशानी दूर करते हुए आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिनके जरिए आप बच्चे की स्लीपिंग क्वालिटी सुधार सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे.....

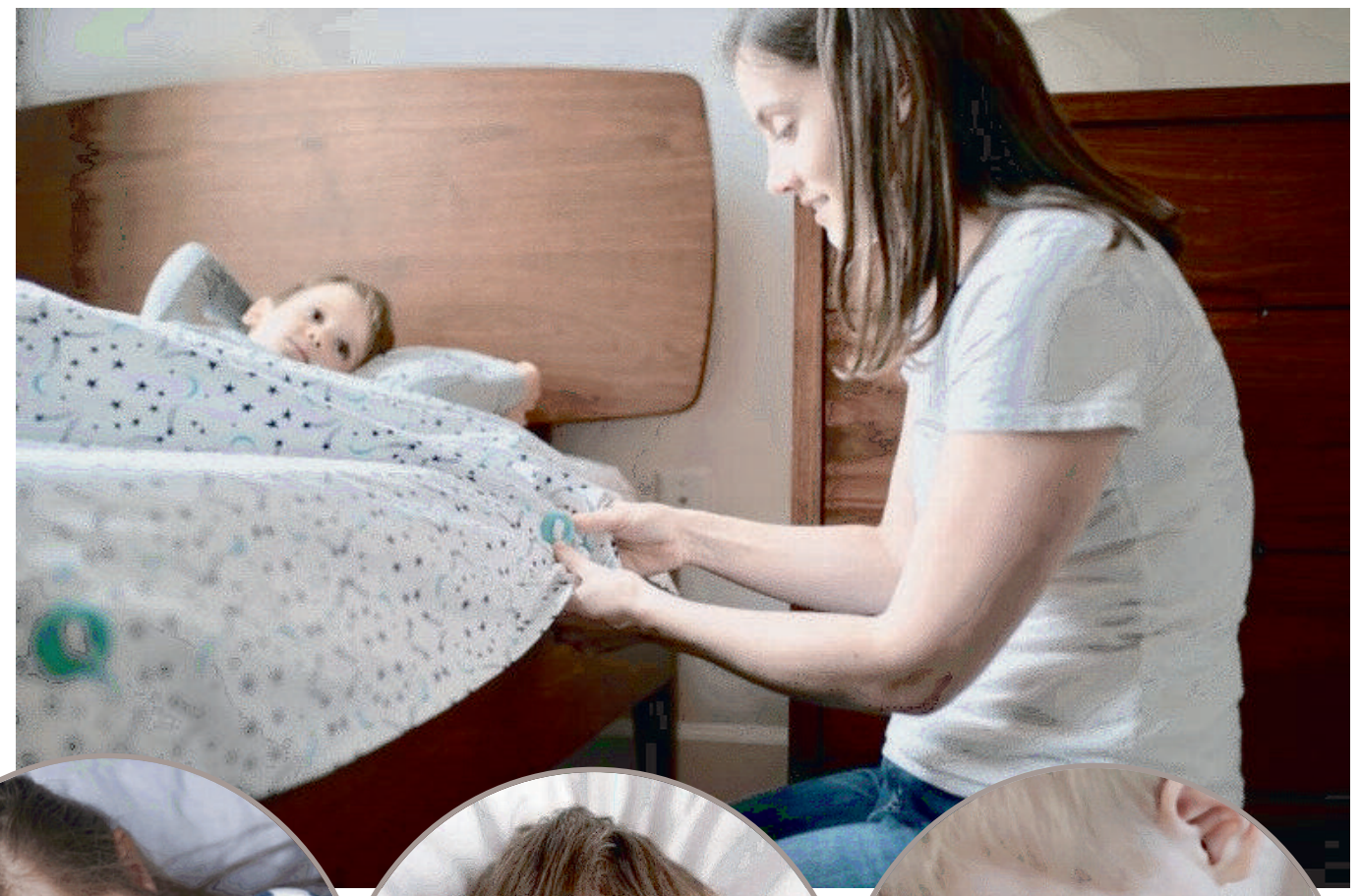

बच्चे हो या फिर बड़े सभी को सोने के लिए एक कंफर्टेबल बिस्तर की जरुरत होती है ऐसे में यदि आप अपने बच्चे के लिए सही बिस्तर का चुनाव करें जिस पर उसे बेहतर नींद आई। कई बार माता-पिता बच्चे के लिए बेहद मुलायम और गद्दे में स्प्रिंग वाले बिस्तर बनाव लेते हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित नहीं होते।

बच्चों को डालें योग की आदत

रोज सुबह उठने के बाद आप बच्चों को एक्सरसाइज और योग करने की आदत डालें। इसके अलावा उन्हें सुबह की रोशनी में पार्क लेकर जाएं और वहां पर उनके साथ समय बिताएं। ऐसा करने से बच्चे चिड़चिड़े नहीं होंगे और उन्हें नींद भी अच्छी आएगी।

एक समय रखें

बच्चे के सोने और जागने का एक समय रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका बच्चा तय समय पर रोजाना सोए और जागे। यदि आपके बच्चे के सोने और जागने का समय फिक्स हो जाएगा तो इससे उसकी बॉडी भी क्लॉक के हिसाब से काम करेगी। इस तरीके से बच्चों को रोज नींद भी अच्छी आएगी।

स्मार्टफोन, टैबलेट से रखें दूर

बच्चों को रात के समय आप स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी से भी दूर ही रखें। इनका ज्यादा इस्तेमाल करनेसे भी बच्चों को रात में अच्छी नींद नहीं आती। ऐसे में बच्चों को आप किताब पढ़कर सोने की डालें। आप चाहें तो खुद ही किताब पढ़कर बच्चों को सुना सकते हैं। इससे उनकी नींद इंप्रूव होगी।

इस बात का भी रखें ध्यान

जब भी बच्चा सोने के लिए जाए तो किसी भी तरह का शोर न करें। शोर होने से भी बच्चे का मन बाकी कामों में लगेगा और उसे नींद अच्छी नहीं आएगी। यदि आप चाहते हैं बच्चों को सुकून भरी नींद आए तो रात के समय कमरे में कम रोशनी रखें।

दिल्ली की सभी सात सीटों पर इस दिन होगा चुनाव, पढ़ें तारीख और उम्मीदवारों की लिस्ट

केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर रही है। चुनाव आयोग ने बताया है कि उसने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। धनबल से लेकर हिंसा तक आयोग कैसे निपटेगा इसका भी खाका तैयार कर लिया है। आयोग ने बताया कि सभी एनफोर्समेंट एंजेंसियों के साथ आयोग तामले बनाए हुए है।

दिल्ली की सात लोकसभा सीट पर खड़े होने वाले प्रत्याशी

लोकसभा क्षेत्र	भाजपा	आप+कांग्रेस
नई दिल्ली (New Delhi)	बांसुरी स्वराज	सोमनाथ भारती
चांदनी चौक (Chandni Chowk)	प्रवीण खंडेलवाल	----
उत्तर-पूर्वी दिल्ली (North-East Delhi)	मनोज तिवारी	----
पश्चिमी दिल्ली (West Delhi)	कमलजीत सहरावत	महाबल मिश्रा
दक्षिणी दिल्ली (South Delhi)	रामवीर सिंह बिधूड़ी	सहीराम पहलवान
पूर्वी दिल्ली (East Delhi)हर्ष मल्होत्रा	कुलदीप कुमार	
उत्तर पश्चिमी दिल्ली (North West Delhi)	योगेंद्र चंदोलिया	------

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही Lok Sabha Elections 2024 का बिगुल बज चुका है। आयोग ने देश की 543 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। सात फेज में होने मतदान होंगे।

चुनाव की तारीखें

19 अप्रैल
26 अप्रैल
7 मई
13 मई चौथा
20 मई
25 मई
1 जून

इसके साथ ही अब यह साफ हो गया है कि दिल्ली के 1,47,18,119 मतदाता किस दिन अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार इस बार भी दिल्ली की सभी सात सीटों पर एक ही दिन मतदान किए जाएंगे। दिल्ली में मतदान छठे चरण यानी 25 मई को चुनाव होंगे।

दिल्ली में इतने हैं मतदाता

अगर मतदाताओं की बात करें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में कुल 1,47,18,119 मतदाता हैं। इनमें से 79,86,572 पुरुष मतदाता और 67,30,371 महिला मतदाता हैं। वहीं 1,176 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।

मतदाताओं के लिहाज से विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा है। यहां 4,28,700 मतदाता हैं। वहीं दिल्ली कैंट सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है, यहां सिर्फ 66,914 मतदाता हैं।

चुनाव की तारीखों का एलान होते ही आया केजरीवाल का बयान

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली की सभी सात सीटों पर छठे चरण में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे।सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि इस बार तानाशाही के खिलाफ वोट करें गुंडागर्दी के खिलाफ वोट करें।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2014 की तारीखों का एलान हो गया है। लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव सात चरणों में होंगे। इस चुनाव के साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव होंगे और चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। दिल्ली की सभी सात सीटों पर छठे चरण में 25 मई को चुनाव होंगे। इसके साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आ गई है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा- देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि इस बार तानाशाही के खिलाफ वोट करें, गुंडागर्दी के खिलाफ वोट करें।

झाड़ू पर वोट करने की अपील की

उन्होंने लिखा- आम आदमी पार्टी लोगों के असल मुद्दों पर काम करती है, जनता को सहूलियतें देती है। जहां-जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं, वहां झाड़ू पर वोट देकर हमारे हाथ मजबूत करें ताकि हम और अधिक ऊर्जा से आपके लिए काम कर सकें।

दिल्ली में आप-कांग्रेस का गठबंधन

बता दें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। चार सीट पर आप ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं तीन सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारने बाकी हैं। वहीं बीजेपी ने सभी सात सीटों पर अपने उम्मीदवार का एलान कर दिया है। इसी के साथ सभी अपनी-अपनी सीटों पर प्रचार में जुट गए हैं।

लोकसभा चुनाव में 'आप' को खलेगी स्टार प्रचारकों की कमी, इन चेहरों पर है सारा दारोमदार

आप इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में गठबंधन में नहीं है जबकि दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा गुजराज गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। आम आदमी दिल्ली में चार गुजरात की दो लोकसभा सीट भरूच और भावनगर पर लड़ रही है। हरियाणा में एक सीट कुरुक्षेत्र से पार्टी लड़ रही है। ये ऐसे राज्य रहे हैं जहां खासकर केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया की डिमांड रही है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के लिए यह लोकसभा चुनाव प्रचार के मामले में सबसे चुनौतीपूर्ण हो गया है। पिछले लोकसभा चुनाव तक पार्टी के पास जिन स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट होती थी, वह इस बार नहीं है। दिल्ली सहित पांच राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ रही आप को पार्टी के बड़े चेहरों में शामिल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया व राज्यसभा संजय सिंह की जरूरत है, मगर ये जेल में हैं।

खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। लगातार समन भेज रही ईडी आम आदमी पार्टी का तनाव बढ़ा रही है। ऐसे हालातों में आप फूंक फूंक कदम रख रही है। आप सभी आशंकाओं को देखते हुए आगे बढ़ रही है। हालांकि आप के पास केजरीवाल के अलावा भगवंत मान, संदीप पाठक जैसे नेता मौजूद हैं, जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आप इस लोकसभा चुनाव में पंजाब में गठबंधन में नहीं है, जबकि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजराज, गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। आम आदमी दिल्ली में चार, गुजरात की दो लोकसभा सीट भरूच और भावनगर पर लड़ रही है। हरियाणा में एक सीट कुरुक्षेत्र से पार्टी लड़ रही है। ये ऐसे राज्य रहे हैं, जहां खासकर केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया की डिमांड रही है। मगर जमीनी स्थिति की बात करें तो आबकारी घोटाले मामले में सिसोदिया और संजय सिंह के जेल में होने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार में अकेले पड़ गए हैं।

मान पर पंजाब में प्रचार की जिम्मेदारी

ईडी के समन व कोर्ट की टिप्पणी से केजरीवाल की मुश्किल भी बढ़ रही है। इससे भी पार्टी के सामने की चुनौती।इधर राघव चड्ढा पहले की तरह सक्रिय नहीं दिख पा रहे हैं। भगवंत मान को लेकर केजरीवाल दूसरे राज्यों में प्रचार करते रहे हैं। मान के लिए पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव प्रचार की भी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। ले देकर आप के पास दिल्ली में केजरीवाल के अलावा आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता हैं, जो दिल्ली की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक हर मंच पर आगे खड़े दिख रहे हैं।

संदीप पाठक पर्दे के पीछे और आगे कर रहे मेहनत

पार्टी में संदीप पाठक ऐसा नाम हैं जो पर्दे के सामने की जगह पर्दे के पीछे ही ज्यादा काम करते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से पार्टी के मंच पर सक्रियता दिखा रहे हैं। हवाला मामले में जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की भले ही पार्टी के बड़े चेहरा के रूप में पहचान न हो, मगर पिछले लोकसभा चुनाव तक वह दूसरे राज्यों में पार्टी के लिए जनसभाओं को संबोधित करते रहे हैं। इससे भी पार्टी को मदद मिलती रही है।

बहरहाल पिछले चुनावों की बात करें तो आप अभी तक तक दो लोकसभा चुनाव लड़ी है, 2014, 2019 के बाद अब 2024 तीसरा चुनाव है।2014 में केजरीवाल स्वयं बनारस जाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने चुनाव लड़े थे। मगर हार जाने के बाद उन्होंने 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है।

आप बनी राष्ट्रीय पार्टी

अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो तब और अब में अंतर यह है कि अब आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, मगर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले कई नेता पार्टी से बाहर हो गए हैं या बाहर कर दिए हैं। इसमें बड़े नेताओं में अंतिम बार 2018 में पार्टी छोड़ने वालों में नेता आशीष खेतान रहे हैं। इससे कुछ समय पहले ही आशुतोष ने आप छोड़ दी थी। कुमार विश्वास भी आप से दूरी बना चुके हैं।

शांति भूषण ने एक करोड़ के दिए थे चंदे

इससे पहले 2015 में आप के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाल दिया गया था और शाजिया इल्मी ने पार्टी से नाता तोड़ लिया था।इसके बाद पार्टी के गंभीर चेहरों में से एक प्रो. आनंद कुमार ने पार्टी से पूरी बना ली थी। आप से पूर्व विधायक विनोद बिन्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी आप से बाहर जाने वालों में शामिल हैं।प्रशांत भूषण के पिता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने आप की स्थापना के समय एक करोड़ की राशि चंदे के रूप में दी थी।

दो राज्यों में आप की पूर्ण बहुमत की सरकार

हालांकि जल्द ही उनका भी पार्टी से मोहभंग हो गया था और वो आम आदमी पार्टी से अलग हो गए थे।वैसे इन नेताओं के बाहर हो जाने के बाद पार्टी आगे बढ़ी है। आज दो राज्यों में आप की पूर्ण बहुमत की सरकार है। गुजराज, गोवा में आप के विधायक हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ और मध्यप्रदेश में आप में आप की मेयर हैं।मगर पहले के चार की जगह लोकसभा सांसद एक बचे हैं।

भ्रष्ट होते तो भाजपा में शामिल होते: AAP

उधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह आम लोगों की पार्टी है। हम में से कोई भी राजनैतिक परिवार से नहीं आता। हमारा प्रचार दिल्ली की जनता करती है, जिनकी सेवा करने का मौका हमें भगवान ने बार बार दिया है।आप ने कहा है कि हम सब बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह के सपने को पूरा करने के लिए साथ आए हैं।हमारी पार्टी में चपे-चपे पर आपको अरविंद केजरीवाल मिलेंगे।आप ने कहा है कि हमारे नेता अपनी ईमानदारी की सज़ा भुगत रहे हैं, भ्रष्ट होते तो भाजपा में शामिल हो कर साफ हो जाते।

दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम डीएम पर 24 हजार का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

हरित क्षेत्र और पार्कों में शादी समेत अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजन से हो रहे प्रदूषण संबंधी मामले में कई आदेश पारित करने के बाद भी नहीं पेश होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दक्षिण-पश्चिम जिलाधिकारी के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डीएम न तो पेश हुए और नहीं कोई आवदेन दाखिल किया।

नई दिल्ली। हरित क्षेत्र और पार्कों में शादी समेत अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजन से हो रहे प्रदूषण संबंधी मामले में कई आदेश पारित करने के बाद भी नहीं पेश होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दक्षिण-पश्चिम जिलाधिकारी के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एनजीटी के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी डीएम न तो वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए और न ही पेशी से छूट के संबंध में कोई आवेदन दाखिल किया। एनजीटी ने कहा कि हमारे पास जिलाधिकारी पर जुर्माना लगाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।

एनजीटी ने नोट किया कि पेश हुए एसडीएम बलराम मीण ने दो टूक शब्दों में कहा कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और किसी कार्यक्रम में फंसे होने के कारण जिलाधिकारी नहीं पेश सकते। एनजीटी ने खेद व्यक्त करते कहा कि एनजीटी के समक्ष वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए एसडीएम बलराम को वीडिया ऑन करने का संकेत दिया गया।

इस पर उन्होंने दूसरे डिवाइस से लॉग-इन करने की बात की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एनजीटी ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा हमारे पास जुर्माना लगाने के साथ ही जेल भेजने का अधिकार है, जिसकी समयसीमा तीन साल तक हो सकती है, लेकिन इस स्तर पर हम ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते।

उक्त तथ्यों को देखते हुए एनजीटी ने जिलाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर मामले पर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही संयुक्त समिति को भी एक सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जिलाधिकारी को छह मई को भौतिक रूप से एनजीटी के सामने पेश होने को कहा।

आवेदनकर्ता विवेक महना ने आवेदन दाखिल करके कहा था कि बिजवासन और भारतल में हरित क्षेत्र के साथ ही पार्कों में विभिन्न लोगों द्वारा शादी समेत अन्य सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन कराकर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इलाके में आने वाले वाहनों से वायु प्रदूषण होने के साथ ही बड़ी मात्रा में कचरा खुले में फेंका जाता है। इसके कारण वायु के साथ जल प्रदूषण हो रहा है।

दिल्ली में झुग्गिवासियों को मिले 1396 फ्लैट्स, अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस; कीमत सिर्फ 1.41 लाख रुपये

दिल्ली के झुग्गीवासियों को डीडीए ने फ्लैट्स आवंटित किए हैं। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार स्थित जेलरवाला बाग में निर्मित कुल 1675 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में से 1396 आवंटित कर दिए। डीडीए का कहना है कि प्रति फ्लैट का निर्माण लागत 25 लाख रुपये है। पात्र लाभार्थी से मात्र 1.41 लाख रुपये लिए गए हैं।

नई दिल्ली। 'जहां झुग्गी वहीं मकान' योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार स्थित जेलरवाला बाग में निर्मित कुल 1675 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में से 1396 आवंटित कर दिए गए हैं। डीडीए का कहना है कि प्रति फ्लैट का निर्माण लागत 25 लाख रुपये है। पात्र लाभार्थी से मात्र 1.41 लाख रुपये लिए गए हैं। इन फ्लैटों में सभी आधुनिक सामाजिक और भौतिक सुविधाएं, सामुदायिक सुविधाएं, सीवेज शोधन व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

ड्रा के माध्यम से फ्लैट आवंटित किए गए

उपराज्यपाल ने जेलरवाला बाग परियोजना के निरीक्षण और उसके बाद की समीक्षा बैठकों में इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिए थे। डीडीए उपाध्यक्ष से अनुमति मिलने के बाद ड्रा के माध्यम से फ्लैट आवंटित किए गए हैं। कुल आवंटित 1396 फ्लैटों में से 1078 फ्लैट जेलरवाला बाग जेजे क्लस्टर के पात्र झुग्गीवासियों को और 318 फ्लैट इसके पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित गोल्डन पार्क रामपुरा और अशोक विहार में माता जय कौर पब्लिक स्कूल के सामने जेजे क्लस्टर के परिवारों को आवंटित किए गए हैं। इससे पहले नवंबर, 2022 में प्रधानमंत्री ने कालका जी में पात्र झुग्गीवासियों को 3024 आधुनिक ईडब्ल्यूएस फ्लैट सौंपे थे।

337 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था

जेलरवाला बाग में डीडीए ने 1675 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाए हैं। 340 वर्ग फुट आकार वाले फ्लैट में एक बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, अलग शौचालय और बाथरूम और एक बालकनी है। इस परियोजना का कुल आवासीय निर्मित क्षेत्र लगभग 67,000 वर्ग मीटर है। सामुदायिक सुविधाओं के लिए कवर्ड क्षेत्र लगभग 1000 वर्ग मीटर है। इसमें 337 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। बचे हुए फ्लैट भी जल्द आवंटित कर दिए जाएंगे।

यह अत्याधुनिक तकनीक विभिन्न विषयों में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

डीजीएक्स ए 100 से सुसज्जित सुपरकंप्यूटिंग केंद्र का उद्घाटन

मैं सुपरकंप्यूटिंग के इस केंद्र को शुरू करने के लिए संस्थान को बधाई देता हूं क्योंकि यह हमारे देश के भविष्य को आकार देगा। मेरा मानना है कि जब छात्र सुपर कंप्यूटर पर काम करना शुरू करेंगे तो वे नए उत्पाद और विचार बनाने में सक्षम होंगे जो परिणाम स्वरुप आर्थिक विकास नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा। यह सराहनीय कार्य है

नई दिल्ली। काईट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली-एनसीआर, गाजियाबाद ने ₹सेंटर ऑफ सुपरकंप्यूटिंग₹ का उद्घाटन समारोह आयोजित किया, जिसमें दुनिया का पहला 5 पेटाफ्लॉप्स AI सुपरकंप्यूटरः NVIDIA DGX A100 शामिल हुआ। सुपरकंप्यूटर, NVIDIA DGX A100 के पीछे की यह अत्याधुनिक तकनीक विभिन्न विषयों में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। यह केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल, 'स्टार्ट इन यूपी' नामक स्टार्ट-अप नीति द्वारा समर्थित है।

कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सुनील कुमार शर्मा - कैबिनेट मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तर प्रदेश सरकार, विशिष्ट अतिथि, संजीव शर्मा महानगर अध्यक्ष – भाजपा) और केशव त्यागी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन कर हुआ। मौके पर अतुल गर्ग अध्यक्ष-गवर्निंग बोर्ड, काईट, सरीश अग्रवाल -अध्यक्ष- कृष्णा चैरिटेबल सोसाइटी, सुनील पी. गुप्ता - महासचिव, जीडी जैन, आदि नारायण गुप्ता, नीरज चौधरी और राकेश गोयल के साथ प्रभारी निदेशक - डॉ. अनिल अहलावत, संयुक्त निदेशक -डॉ. मनोज गोयल और अतिरिक्त निदेशक - डॉ. शैलेश तिवारी मौजूद रहे ।

सुनील कुमार शर्मा ने कहा, "मैं सुपरकंप्यूटिंग के इस केंद्र को शुरू करने के लिए संस्थान को बधाई देता हूं क्योंकि यह हमारे देश के भविष्य को आकार देगा। मेरा मानना है कि जब छात्र सुपर कंप्यूटर पर काम करना शुरू करेंगे, तो वे नए उत्पाद और विचार बनाने में सक्षम होंगे जो परिणाम स्वरुप आर्थिक विकास, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा।"

गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग , ने कहा, "एनवीडिया डीजीएक्स ए100 सुपरकंप्यूटर के माध्यम से हम अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर प्रदान करना चाहते हैं। मैं सभी संकाय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे बच्चों को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए सभी तकनीकी सुविधाएं प्रदान करें।"

परिसर में लॉन्च किए गए सुपरकंप्यूटिंग केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए, डॉ. रेखा कश्यप, एचओडी सीएसई एआई और सीएसई एआईएमएल ने बताया कि ₹एनवीडिया डीजीएक्स ए100 दुनिया का पहला 5 पेटाफ्लॉप्स एआई सिस्टम है, जिसे प्रशिक्षण, अनुमान और विश्लेषण को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सुपरकंप्यूटिंग केंद्र में डीजीएक्स ए100 सिस्टम को शामिल करना हमारे संस्थान की अनुसंधान क्षमताओं के एक नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। अद्वितीय कम्प्यूटेशनल दक्षता और बहुमुखी प्रतिभा के साथ, DGX A100 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, जलवायु विज्ञान, जीनोमिक्स और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान को गति देगा।

संयुक्त निदेशक डॉ. मनोज गोयल ने डॉ. रेखा कश्यप और डीन आईटीएस डॉ. आदेश पांडे को कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु बधाई देते हुए कहा, ₹डीजीएक्स ए100 का एकीकरण शैक्षणिक कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जिससे छात्रों को अत्याधुनिक एआई तकनीक का उपयोग करके व्यावहारिक अनुभव मिलेगा।

कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और संस्थान की ओर से मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने के साथ हुआ। सुपरकंप्यूटिंग केंद्र के भव्य उद्घाटन समारोह को देखने के लिए कॉलेज के छात्र, डीन, प्रमुख, कार्यात्मक प्रमुख और संकाय सदस्य उपस्थित थे।

पहले और अब के मुकाबले लोकसभा चुनावों में आया बड़ा बदलाव, पहाड़ों में छह महीने पहले मच जाता था शोर

भारत विश्व के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। देश की 140 करोड़ की जनता एक बार फिर से नई सरकार चुनने को तैयार है। राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। सांसद बनने के सपने देख रहे विभिन्न पार्टियों के दावेदार प्रत्याशी इंटरनेट मीडिया के जरिये प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ दल-बल के साथ घरों में दस्तक दे रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा। भारत विश्व के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। देश की 140 करोड़ की जनता एक बार फिर से नई सरकार चुनने को तैयार है। राजनीतिक दलों ने चुनाव में अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। सांसद बनने के सपने देख रहे विभिन्न पार्टियों के दावेदार प्रत्याशी इंटरनेट मीडिया के जरिये प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ दल-बल के साथ घरों में दस्तक दे रहे हैं।

पहले और अब के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। यह कहना है एडब्ल्यूएचओ सोसाइटी में रहने वाले 85 वर्षीय मेजर कुंवर सिंह राणा का। मूलरूप से हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना गांव पराह के रहने वाले कुंवर सिंह राणा बताते हैं कि पुराने समय में पार्टियां छह महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों को घोषित कर देती थीं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ज्यादातर गांवों में पार्टी प्रत्याशी चुनाव से कई महीनों पहले ही पहुंचकर प्रचार-प्रसार करते थे। पैदल ही अपने समर्थकों के साथ घर-घर पहुंचते थे। प्रत्याशियों के एजेंट गांवों में घूमकर पार्टी प्रत्याशियों से जुड़े बिल्ला बांटकर प्रचार किया करते थे। बच्चों में बिल्ला एकत्र करने की होड़ मची रहती थी। उन्होंने कई मतदान देखे हैं।

पहले और अब के मतदान में काफी बदलाव आया है। पहले मतदान प्रतिशत बेहद कम रहता था। लोकतंत्र के महापर्व में महिलाओं की सहभागिता बेहद कम रहती थी। गिनी-चुनी पार्टियां और गिने चुने ही प्रत्याशी होते थे। पहले लोकसभा चुनाव में हर एक उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर नाम व चुनाव चिह्न के साथ अलग रंगीन पेटी दी गई थी। इसका एकमात्र मकसद यह था कि अनपढ़ लोग भी अपनी पसंद के उम्मीदवार को आसानी से वोट दे सके। उस समय 85 प्रतिशत लोग अशिक्षित थे। संचार का कोई भी ऐसा माध्यम नहीं था, जो लोगों तक सीधी अपनी पहुंच रखता हो। उस दौर में टेलीविजन नहीं था। रेडियो की संख्या भी बेहद कम थी। लोकतंत्र को लेकर लोगों में जागरूकता न के बराबर थी। चुनाव आयोग के सामने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना सबसे बड़ी चुनौती होती थी। चुनाव आयोग ने वर्तमान प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाते हुए काफी बदलाव किया है।

गाजियाबाद में इस तारीख को होगी वोटिंग, इस सीट पर कई बार रहा BJP का कब्जा

चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेस में 2024 लोक सभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। गाजियाबाद में वोटिंग की तारीख की घोषणा हो चुकी है। जिले की सभी पांच विधानसभा के अलावा हापुड़ की धौलाना आंशिक क्षेत्र में कुल 2938845 मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इनमें 1622869 पुरुष और 1315782 महिला मतदाता दर्ज हैं।

गाजियाबाद। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही 2024 के महासमर की रणभेरी बज चुकी है। आज चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ ही कई राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी एलान किया।

इसी के साथ ही गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की तारीख भी घोषित हो चुकी है। यहां पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके बाद 4 जून को मतों की गिनती होगी। अभी तक यहां पर किसी भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी का एलान नहीं किया है।

जिले में पांच विधानसभा क्षेत्र शामिल : अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार, जिले की सभी पांच विधानसभा के अलावा हापुड़ की धौलाना आंशिक क्षेत्र में कुल 29,38,845 मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इनमें 16,22,869 पुरुष और 13,15,782 महिला मतदाता दर्ज हैं।

पति की हत्या के मामले की पैरवी कर रही महिला पर एसिड अटैक, बाइक सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम

गाजियाबाद में पति की दो साल पहले हुई हत्या के मामले में पैरवी कर रही महिला पर युवकों ने तेजाब फेंक दिया। घटना को पटेल नगर में बाइक सवार दो युवकों ने अंजाम दिया। महिला इसमें बुरी तरह झुलस गई और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अखिलेश कुमार को तीन मई 2022 को कवि नगर औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में जला दिया गया था।

गाजियाबाद। पति की दो वर्ष पहले हुई हत्या के मामले में पैरवी कर रही महिला पर पटेल नगर में बाइक सवार दो लोगों ने तेजाब फेंक दिया। महिला इसमें बुरी तरह झुलस गई और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के बेटे शिवम ने बताया कि उनके पिता अखिलेश कुमार को तीन मई 2022 को कवि नगर औद्योगिक क्षेत्र के स्वदेशी कंपाउंड में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में जला दिया गया था। इलाज के दौरान 29 मई को उनके पिता की मौत हो गई। इस मामले में तीन लोगों पर कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज है। पहले वह दौलतपुर क्षेत्र में रहते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद नंदग्राम में आकर रहने लगे।

बाइक सवार युवकों ने फेका तेजाब

शनिवार दोपहर शिवम की मां सुमन पंचवटी से राशन लेकर ई-रिक्शा में बैठकर नंदग्राम आ रही थी। महिला का आरोप है कि पटेल नगर में निम गैस एजेंसी के पास बाइक सवार दो लोगों ने उनके उपर तेजाब फेंक दिया। महिला को यशोदा अस्पताल भर्ती कराया जा रहा है।

काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े 11 फैक्ट्स

(१) : - काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दो भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में मां भगवती विराजमान हैं। दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप (सुंदर) रूप में विराजमान हैं। इसीलिए काशी को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है।

(२) : - देवी भगवती के दाहिनी ओर विराजमान होने से मुक्ति का मार्ग केवल काशी में ही खुलता है। यहां मनुष्य को मुक्ति मिलती है और दोबारा गर्भधारण नहीं करना होता है। भगवान शिव खुद यहां तारक मंत्र देकर लोगों को तारते हैं। अकाल मृत्यु से मरा मनुष्य बिना शिव अराधना के मुक्ति नहीं पा सकता।

(*) : - श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं, जो अद्भुत है। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है।

(४) : - विश्वनाथ दरबार में गर्भ गृह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है। तांत्रिक सिद्धि के लिए ये उपयुक्त स्थान है। इसे श्री यंत्र-तंत्र साधना के लिए प्रमुख माना जाता है।

(५) : - बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से चार प्रमुख द्वार इस प्रकार हैं :-

(१) : - शांति द्वार।

(२) : - कला द्वार।

(*) : - प्रतिष्ठा द्वार।

(४) : - निवृत्ति द्वार।

इन चारों द्वारों का तंत्र में अलग ही स्थान है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां शिवशक्ति एक साथ विराजमान हों और तंत्र द्वार भी हो।

(६) : - बाबा का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। इस कोण का मतलब होता है, संपूर्ण विद्या और हर कला से परिपूर्ण दरबार। तंत्र की 10 महा विद्याओं का अद्भुत दरबार, जहां भगवान शंकर का नाम ही ईशान है।

(७) : - मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण मुख पर है और बाबा विश्वनाथ का मुख अघोर की ओर है। इससे मंदिर का मुख्य द्वार दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करता है। इसीलिए सबसे पहले बाबा के अघोर रूप का दर्शन होता है। यहां से प्रवेश करते ही पूर्व कृत पाप-ताप विनष्ट हो जाते हैं।

(८) : - भौगोलिक दृष्टि से बाबा को त्रिकंटक विराजते यानि त्रिशूल पर विराजमान माना जाता है। मैदागिन क्षेत्र जहां कभी मंदाकिनी नदी और गौदोलिया क्षेत्र जहां गोदावरी नदी बहती थी। इन दोनों के बीच में ज्ञानवापी में बाबा स्वयं विराजते हैं। मैदागिन-गौदौलिया के बीच में ज्ञानवापी से नीचे है, जो त्रिशूल की तरह ग्राफ पर बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकता।

(९) : - बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान है। वह दिनभर गुरु रूप में काशी में भ्रमण करते हैं। रात्रि नौ बजे जब बाबा का श्रृंगार आरती किया जाता है तो वह राज वेश में होते हैं। इसीलिए शिव को राजराजेश्वर भी कहते हैं।

(१०) : - बाबा विश्वनाथ और मां भगवती काशी में प्रतिज्ञाबद्ध हैं। मां भगवती अन्नपूर्णा के रूप में हर काशी में रहने वालों को पेट भरती हैं। वहीं, बाबा मृत्यु के पश्चात तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। बाबा को इसीलिए ताड़केश्वर भी कहते हैं।

(११) : - बाबा विश्वनाथ के अघोर दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। शिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ औघड़ रूप में भी विचरण करते हैं। उनके बारात में भूत, प्रेत, जानवर, देवता, पशु और पक्षी सभी शामिल होते हैं।

समाजवादी पार्टी की पांचवीं सूची जारी, गौतमबुद्ध नगर से इन्हें बनाया उम्मीदवार

समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों की पांचवीं सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार को एलान कर दिया है। लखनऊ में हुई बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बनी है जिसके बाद शनिवार शाम को उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं।

नोएडा। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों की पांचवीं सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार को एलान कर दिया है। लखनऊ में हुई बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बनी है, जिसके बाद शनिवार शाम को उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं।

सपा गठबंधन की ओर से डॉक्टर महेन्द्र नागर को गौतमबुद्ध नगर की लोकसभा सीट से उतारा है। महेंद्र नागर का मुकाबला भाजपा के वर्तमान सांसद महेश शर्मा से होगा। भाजपा ने इन्हें फिर से गौतमबुद्ध नगर से उम्मीदवार बनाया है।

लोकसभा चुनावों में कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमट सकती है

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदले समीकरणों ने जहां दूसरे दलों के लिए नई संभावनाएं जगाईं, वहीं कांग्रेस को अपनों से मायूसी ही मिलती गई। 1984 में 51.03 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली कांग्रेस फिर ऐसे जनाधार को वापस नहीं हासिल कर सकी।

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस कांग्रेस का हमेशा अपर हैंड रहता था, वह अब दूसरों के रहम-ओ-करम पर राजनीति करने को मजबूर हो गई है। प्रदेश में ना उसका वोट बैंक बचा है, ना नेता और संगठन। हाँ, यदि हवा-हवाई बातों से पार्टी को फायदा हो पाता तो जरूर यूपी में कांग्रेस टॉप पर होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज का मतदाता अपने नेताओं पर बारीकी से नजर रखता है। इस कसौटी में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और गांधी परिवार पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। कांग्रेस के विधान सभा और लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के आंकड़े भी चुनाव-दर-चुनाव उसके जनाधार खिसकने के साक्षी हैं। यह गिरावट 1984 के बाद चार दशक में आई है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 85 सीटों (तब उत्तराखंड की भी पांच सीटें शामिल) पर चुनाव लड़ी थी और 83 सीटों पर जीत हासिल की थी। भले ही तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के साथ जनभावनाओं का ज्वार था, जिसके सहारे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन के शिखर को छुआ। यह वह दौर था जब राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का एकछत्र राज था और बीजेपी की एंट्री भर हुई थी, लेकिन उसकी राजनैतिक विचारधारा कांग्रेस से उलट थी। बीजेपी तुष्टिकरण की जगह हिन्दुत्व की बात करती थी। अयोध्या, काशी और मथुरा उसके एजेंडे में प्रमुख रूप से शामिल थे, जिससे कांग्रेस हमेशा किनारा करती रही थी। वहीं क्षेत्रीय दलों के रूप में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जातिवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। प्रदेश की राजनीति में बदले समीकरणों ने जहां दूसरे दलों के लिए नई संभावनाएं जगाईं, वहीं कांग्रेस को अपनों से मायूसी ही मिलती गई। 1984 में 51.03 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली कांग्रेस फिर ऐसे जनाधार को वापस नहीं हासिल कर सकी। आज उसका जनाधार दो प्रतिशत में सिमट गया है।

दरअसल, प्रदेश में सपा व बसपा के उदय के साथ ही कांग्रेस पीछे होती गई और भाजपा की प्रखर हिंदुत्व वाली छवि ने उसकी राह और मुश्किल कर दी। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे। सपा के उदय के साथ मुस्लिम कांग्रेस से छिटक कर उसके पाले में चला गया। बसपा ने कांग्रेस के दलित वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस से मोहभंग के बाद ब्राह्मणों ने भाजपा का दामन थाम लिया। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने के बाद की बात की जाए तो कांग्रेस वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर लड़ी थी और 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले ढाई दशक में यह कांग्रेस का सर्वाधिक उत्साहित करने वाला प्रदर्शन था। इसके पीछे कांग्रेस की मनरेगा व खाद्य सुरक्षा को लेकर नीतियों की बड़ी भूमिका मानी गई थी। कांग्रेस केंद्र में दोबारा सरकार बनाने में सफल हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी साख को बचाए रखने में कामयाब नहीं रही।

उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिय पार्टी ने कई प्रयोग भी किए। राहुल गांधी को यूपी में पैर पसारने के लिये खुली छूट दी गई, इसके नतीजे उत्साहवर्धक नहीं आये तो प्रियंका वाड्रा को प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन बूथ स्तर पर कमजोर हुई पार्टी के सामने कार्यकर्ताओं में पुराना जोश भरना सपना ही रहा। उधर, कांग्रेसी नेता आपस में टांग खिंचाई करते रहे, जिसकी वजह से पार्टी में अंतरकलह भी बढ़ता गया। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 2009 का अपना प्रदर्शन दोहराने को तरसती ही रही। नेहरू-गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से गहरा रिश्ता होने के बाद भी पार्टी खोया दमखम नहीं जुटा सकी। पिछले चुनाव में कांग्रेस रायबरेली की एकमात्र सीट पर ही जीत का स्वाद चख सकी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी तक हार गये। जबकि रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी अबकी बार सदन में जाने के लिये राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं। इस बार वह भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने के साथ ही परंपरागत सीट अमेठी व रायबरेली में अपनी साख को बचाए रखने की चुनौती से जूझ रही है।

इससे निपटने के लिए पार्टी सपा से गठबंधन के तहत उसके हिस्से आईं 17 सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। प्रदेश मुख्यालय में वार रूम की स्थापना की गयी है और अमेठी व रायबरेली समेत 17 लोकसभा सीटों के 34 हजार बूथों पर एजेंट जुटाए जा रहे हैं। वार रूम के सदस्य संजय दीक्षित के अनुसार, 17 लोकसभा क्षेत्रों में अब तक 18 हजार बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जा चुके हैं। शेष को भी जल्द नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा वार रूम के 10 डेस्क हेड भी बनाए गए हैं और सभी को आठ-आठ लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार सभी 80 लोकसभा सीटों पर बूथ स्तर पर संगठन को खड़ा किया जा रहा है। कुल मिलाकर यूपी से अपने नेताओं को संसद भेजने के लिये कांग्रेस को शून्य से सफर शुरू करना होगा और इसके लिये उसके सिर्फ 17 प्रत्याशी मैदान में होंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए यूपी में कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें देने के लायक ही समझा है।

प्रदेश में सपा व बसपा के उदय के साथ ही कांग्रेस पीछे होती गई और भाजपा की प्रखर हिंदुत्व वाली छवि ने उसकी राह और मुश्किल कर दी। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे। सपा के उदय के साथ मुस्लिम कांग्रेस से छिटक कर उसके पाले में चला गया। बसपा ने कांग्रेस के दलित वोटबैंक पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस से मोहभंग के बाद ब्राह्मणों ने भाजपा का दामन थाम लिया।

वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने के बाद की बात की जाए तो कांग्रेस वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर लड़ी थी और 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले ढाई दशक में यह कांग्रेस का सर्वाधिक उत्साहित करने वाला प्रदर्शन था। इसके पीछे कांग्रेस की मनरेगा व खाद्य सुरक्षा को लेकर नीतियों की बड़ी भूमिका मानी गई थी। कांग्रेस केंद्र में दोबारा सरकार बनाने में सफल हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी साख को बचाए रखने में कामयाब नहीं रही।

पार्टी ने फिर कई प्रयोग भी किए। प्रियंका वाड्रा को प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन बूथ स्तर पर कमजोर हुई पार्टी के सामने कार्यकर्ताओं में पुराना जोश भरना सपना ही रहा। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इसके पीछे पार्टी में अंतरकलह को भी बड़ी वजह मानते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 2009 का अपना प्रदर्शन दोहराने को तरसती ही रही। नेहरू-गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से गहरा रिश्ता होने के बाद भी पार्टी खोया दमखम नहीं जुटा सकी। पिछले चुनाव में कांग्रेस रायबरेली की एकमात्र सीट पर ही जीत का स्वाद चख सकी थी। 1998 का लोकसभा चुनाव ऐसा था, जिसमें कांग्रेस के हिस्से एक भी सीट नहीं आई थी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने के साथ ही परंपरागत सीट अमेठी व रायबरेली में अपनी साख को बचाए रखने की चुनौती से जूझ रही है। इससे निपटने के लिए पार्टी सपा से गठबंधन के तहत उसके हिस्से आईं 17 सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है।

Maruti EVX: मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी में मिलेंगे कैसे फीचर्स, SPY इमेज में मिली जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

Maruti सुजुकी की ओर से आने वाले कुछ महीनों में अपनी पहली Electric SUV EVX को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च से पहले कंपनी EVX की टेस्टिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान गाड़ी को स्पॉट किया गया। जिसमें कुछ फीचर्स की जानकारी मिली है। Maruti EVX में किस तरह के फीचर्स को दे सकती है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी Maruti की ओर से जल्द ही पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी EVX को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करने से पहले कई तरह के टेस्ट का सामना कर रही है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई गाड़ी में किस तरह के फीचर्स की जानकारी मिली है।

मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेकर कई बार कुछ जानकारियां सामने आ चुकी हैं। लेकिन हाल में ही इस गाड़ी के टेस्टिंग वर्जन को फिर से स्पॉट किया गया है। जिसके बाद इस गाड़ी में मिलने वाले कुछ और फीचर्स की जानकारी सामने आई हैं।

कैसे होंगे फीचर्स

ईवीएक्स की टेस्टिंग के दौरान जो जानकारी सामने आई है, उसमें गाड़ी के कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर के फीचर्स की डिटेल शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से इस पांच सीटों वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी में आगे के फेंडर पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। जबकि पिछले दरवाजों के हैंडल को पिलर पर दिया गया है। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा, ADAS, इंटीग्रेटिड स्पॉयलर, एलईडी लाइट्स, हाई माउंटिड स्टॉप लैंप, शॉर्क फिन एंटीना, डिजिटल कंसोल, हेड अप डिस्प्ले, वायरलैस चार्जर, ड्यूल जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंबिएंट लाइट जैसे कई फीचर्स को दिया जा सकता है।

कितनी मिलेगी रेंज

कंपनी की ओर से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की रेंज को लेकर पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। कंपनी के मुताबिक इस एसयूवी को फुल चार्ज के बाद 550 किलोमीटर तक चलाया जा सकेगा। एसयूवी को इतनी दूरी तक ले जाने के लिए 60kWh की क्षमता का बैटरी पैक दिया जाएगा।

कॉन्सेप्ट वर्जन दिखा चुकी है मारुति

मारुति सुजुकी की ओर से पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर ईवीएक्स के कॉन्सेप्ट वर्जन को साल 2023 के दौरान ऑटो एक्सपो में सबसे पहले दिखाया गया था। इसके बाद इस गाड़ी को कंपनी ने फरवरी 2024 में हुए भारत मोबिलिटी इवेंट में भी शोकेस किया था।

कार का इन्श्योरेंस समय पर रिन्यू करवाना क्यों जरूरी है? जानें डिटेल

देश में हर महीने बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री होती है। जिनके साथ तो इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है। लेकिन कई लोग लापरवाही या समय की कमी के कारण अपनी पुरानी car का Insurance समय पर रिन्यू नहीं करवा पाते। समय पर कार के इंश्योरेंस को रिन्यू न करवाने पर किस तरह के नुकसान हो सकते हैं। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में हर साल लाखों की संख्या में नई कारों को खरीदा जाता है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुरानी कारों को भी बेचा जाता है। लेकिन अक्सर लोग कार खरीदने के बाद Car Insurance पॉलिसी को रिन्यू करवाने में लापरवाही बरतते हैं और इसका नुकसान उनको बाद में होता है। हम इस खबर में आपको ऐसे कुछ कारणों की जानकारी दे रहे हैं, जो समय पर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू न करवाने के कारण होते हैं।

जरूरी है Car Insurance

किसी भी कार के लिए इंश्योरेंस पॉलिस का होना काफी जरूरी होता है। अगर किसी कारण से कार की इंश्योरेंस पॉलिसी की वैधता खत्म हो जाए और उस रिन्यू न करवाया जाए तो कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ ही बिना वजह आपकी जेब पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है।

वैधता खत्म होने के बाद रिन्यू में परेशानी

अगर एक बार किसी कार की इंश्योरेंस पॉलिसी की वैधता खत्म हो जाती है, तो फिर उसे रिन्यू करवाने में परेशानी होती है। पॉलिसी के वैध रहते अगर इंश्योरेंस को रिन्यू करवाया जाता है तो यह काफी आसानी से हो जाती है। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी एजेंट के जरिए संपर्क कर रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन वैधता खत्म होने के बाद पॉलिसी रिन्यू होने में आपका समय भी लगता है और गाड़ी की फिर से वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है।

हादसे का खतरा

अगर कार की इंश्योरेंस पॉलिसी वैध है और तब कोई हादसा हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देकर क्लेम लिया जा सकता है। लेकिन अगर पॉलिसी की वैधता ही खत्म हो जाए और तब कोई हादसा हो जाए तो ऐसे में कार को ठीक करवाने के लिए मालिक को पैसा खर्च करना पड़ता है। जो पॉलिसी के खर्च से काफी ज्यादा हो सकता है।

पुलिस कर सकती है कार्रवाई

अगर बिना वैध इंश्योरेंस पॉलिसी आप कार को सड़क पर चलाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की जा सकती है। कई मामलों में पुलिस की ओर से हजारों रुपये का चालान भी किया जाता है। जिससे बचने के लिए पॉलिसी रिन्यू करवाना बेहतर रहता है।

बिना खरीदे हुए किराए पर मारुति की किन गाड़ियों को चलाना पसंद करते हैं लोग, जानें डिटेल

मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी की ओर से देशभर में कई तरह के वाहनों की बिक्री की जाती है। Maruti Subscribe Program के तहत कंपनी की किन गाड़ियों को बिना खरीदे भी चलाया जा सकता है। कंपनी के इस प्रोग्राम ने क्या नई उपलब्धि को हासिल किया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की ओर से कुछ सालों पहले एक अलग तरह की स्कीम को Maruti Subscribe Program के नाम से शुरू किया गया था। इस खबर में आपको बता रहे हैं कि कंपनी की किन कारों को इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और मारुति ने इस स्कीम से क्या नया मुकाम हासिल किया है।

मिलता है यह ऑफर

भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से कई तरह के सेगमेंट में कारों को ऑफर किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही कंपनी की ओर से एक खास प्रोग्राम Maruti Subscribe Program को भी चलाया जाता है। इस तरह के प्रोग्राम का फायदा यह होता है कि कार खरीदने के लिए लाखों रुपये खर्च किए बिना ही कार को एक निश्चित अवधि के लिए तय कीमत पर चलाया जा सकता है। इसके तहत कार को किराए पर लेने के बाद उसके रख-रखाव, सर्विस, इंश्योरेंस में खर्च होने वाले रुपये की बचत हो जाती है।

हासिल किया नया मुकाम

कंपनी ने इस प्रोग्राम को साल 2020 में शुरू किया था। चार सालों में देशभर में इस प्रोग्राम से 10 हजार लोग जुड़ चुके हैं। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हाल में ही इस प्रोग्राम ने 10 हजार सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा पार किया है। कंपनी इस प्रोग्राम को देशभर के 25 शहरों में चलाती है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान ही इसमें 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है।

पसंद है ये कारें

मारुति के इस प्रोग्राम में कंपनी कई कारों को ऑफर करती है। लेकिन सबसे ज्यादा बलेनो, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और अर्टिगा को पसंद किया जाता है। करीब 53 फीसदी ग्राहकों ने इस प्रोग्राम के तहत इन गाड़ियों को चुना। इसके साथ ही इस सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम में तीन से चार साल तक के लिए सबसे ज्यादा लोगों ने सदस्यता ली। कंपनी के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलौर में इस प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा ग्राहक हैं।

टॉप 10 कार: 5.54 लाख की Wagon R ने किया कमाल, जानें बिक्री के मामले में क्या है टॉप-10 कारों का हाल

फरवरी 2024 के दौरान देशभर में करीब तीन लाख से ज्यादा यात्री वाहनों की बिक्री हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 के दूसरे महीने में किस कंपनी की किस कार को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। बिक्री के मामले में Top 10 cars की लिस्ट में कौन कौन सी कंपनियों की कारों को शामिल किया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में हर महीने बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री होती है। यात्री वाहन सेगमेंट में भी कारों की बिक्री काफी ज्यादा होती है। फरवरी 2024 के दौरान किस कंपनी की कार को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। साथ ही Top 10 cars की लिस्ट में किसके नाम शामिल हुए। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

मारुति वैगन आर

मारुति सुजुकी की Wagon R कार बीते महीने में सबसे ज्यादा भारतीयों की पसंद बनी। फरवरी 2024 में इस 5.54 लाख रुपये की इस कार ने अन्य सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 पोजिशन को अपने नाम किया। जानकारी के मुताबिक इस कार की कुल 19412 यूनिट्स की बिक्री फरवरी 2024 में हुई। जबकि फरवरी 2023 के दौरान इसकी कुल 16889 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

टाटा पंच

देश की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता Tata की Punch इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही। इस माइक्रो एसयूवी की फरवरी 2024 के दौरान कुल 18438 यूनिट्स की बिक्री हुई। जबकि पिछले साल फरवरी महीने में 11169 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

मारुति बलेनो

मारुति सुजुकी की प्रीमियम हैचबैक बलेनो को भी बीते महीने में काफी पसंद किया गया। नेक्सा डीलरशिप के जरिए ऑफर की जाने वाली बलेनो की फरवरी 2024 में कुल 17517 यूनिट्स की बिक्री हुई। जबकि फरवरी 2023 में इस प्रीमियम हैचबैक को 18592 लोगों ने खरीदा था।

मारुति डिजायर

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की ओर से भी काम्पैक्ट सेडान के तौर पर डिजायर को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस बेहतरीन कार को बीते महीने में 15837 लोगों ने खरीदा। फरवरी 2023 में इस सेडान कार को 16798 लोगों ने खरीदा था।

अन्य कारों का हाल

टॉप-5 के साथ ही मारुति अर्टिगा इस लिस्ट में छठे नंबर पर रही। इस एमपीवी की कुल 15519 यूनिट्स बीते महीने में ग्राहकों ने खरीदीं। इसके बाद हुंडई की क्रेटा को 15276, महिंद्रा स्कॉर्पियो को 15051, टाटा नेक्सन को 14395 और मारुति फ्रॉन्क्स को 14168 ग्राहकों ने खरीदा।

Citroen C3X: सिट्रॉएन की पहली सेडान कार जल्द होगी लॉन्च, जानें कितना दमदार होगा इंजन और कैसे होंगे फीचर्स

फ्रेंच कार निर्माता Citroen की ओर से भारत में अपना पोर्टफोलियो जल्द बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से आने वाले कुछ महीनों में एक नई गाड़ी C3X को लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी की ओर से पहली सेडान कार को किस तरह के फीचर्स और इंजन के साथ लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। Citroen की ओर से जल्द ही नई सेडान कार C3X को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से इस कार में किस तरह की क्षमता का इंजन और किस तरह के फीचर्स को दिया जा सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Citroen लाएगी नई C3X

भारत लगातार दुनियाभर के वाहन निर्माताओं के लिए बड़ा बाजार साबित हो रहा है। ऐसे में कई कंपनियों की ओर से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया जा रहा है और कुछ कंपनियां अपने मौजूदा वाहनों को अपडेट कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिट्रॉएन की ओर से भी जल्द ही भारतीय बाजार में अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से जल्द ही नई सेडान कार C3X को लाया जा सकता है।

कितना दमदार इंजन

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी भारत में अपनी कई कारों में 1.2 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन का उपयोग करती है। उम्मीद की जा रही है कि इसी इंजन का उपयोग जल्द आने वाली C3X में किया जा सकता है। इस इंजन से कार को 110 पीएस की पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इस इंजन के साथ कंपनी मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दे सकती है।

कैसे होंगे फीचर्स

सिट्रॉएन की नई C3X सेडान कार में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वायरलैस चार्जर, एलईडी लाइट्स, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और की-लैस एंट्री के साथ ही ऐसे कई फीचर्स को दिया जा सकता है। जिनको कंपनी अपनी मौजूदा सी3 हैचबैक कार में ऑफर करती है।

कब होगी लॉन्च

कंपनी की ओर से अभी इस कार के लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के मध्य तक सिट्रॉएन की ओर से नई कार को पेश किया जा सकता है।

डर कर काम करता है सरकारी तंत्र

योगेंद्र योगी

सरकारी मशीनरी डंडे के जोर से काम करती है। इसका उदाहरण चुनावी बांड के खुलासे से हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने इस मामले को टरकाने के प्रयास किए, किन्तु सुप्रीम कोर्ट के सामने दाल नहीं गल सकी।

सीबीआई की तरह एसबीआई की चुनावी फंड के मामले में हुई किरकिरी से साबित हो गया है कि पिंजरे का तोता सिर्फ एक ही विभाग नहीं है। सरकारी विभाग सत्तारूढ़ दलों की कठपुतलियों की तरह काम करते हैं। सत्ता बदलते ही दूसरे दलों की भाषा बोलने लगते हैं। पारदर्शिता को लेकर सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए'

सरकारी मशीनरी डंडे के जोर से काम करती है। इसका उदाहरण चुनावी बांड के खुलासे से हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने इस मामले को टरकाने के प्रयास किए, किन्तु सुप्रीम कोर्ट के सामने दाल नहीं गल सकी। बांड के जरिए चुनावी चंदा देने वाले उद्योगपतियों के नाम और राशि छिपाने के एसबीआई के सारे प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया।

एसबीआई की मंशा थी कि इस चंदे के मामले का खुलासा जून महीने के बाद किया जाए ताकि लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने के बाद इस मामले को आने वाली केंद्र सरकार संभाल सके। एसबीआई ने इस बांड खुलासे की अवधि को लंबा खींचने के लिए कई तरह के बहाने बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कह दिया कि यदि निर्धारित तारीख तक इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई और चंदे का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग ने 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा को जारी किया था। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा वही डेटा है जिसे चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को एसबाआई ने शेयर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी किए गए हैं। इसमें कुल 763 पन्ने हैं जिनमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और लोगों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के सामने एसबीआई ने घुटने टेक दिए। जिस विवरण को जुटाने के लिए जून माह तक समय मांगा जा रहा था, उसे एसबीआई ने चंद दिनों में ही पूरा कर दिखाया। इससे जाहिर है कि कार्रवाई के भय से सरकारी तंत्र तूफान की गति से काम कर सकता है। सरकारी मशीनरी में लगी जंग तभी हटती है, सुप्रीम कोर्ट जैसे आदेशों की पालना करनी होती है। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी सरकारी विभाग ने कोर्ट के भय के मारे घोड़े की गति से काम किया है।

कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो इसका दूसरा बड़ा उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कानून मंत्री और पीएमओ की दखलअंदाजी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख शब्दों में कहा था कि सीबीआई के कई मास्टर हैं और जांच एजेंसी पिंजड़े में कैद तोते जैसी है। सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब सीबीआई स्वतंत्र ही नहीं है तो वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है जबकि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और उसे अपनी स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। सीबीआई को एक तोते की तरह अपने मास्टर की बातें नहीं दोहरानी चाहिए। एसबीआई ने भी सीबीआई की तरह व्यवहार किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को सख्ती दिखाने पर विवश होना पड़ा। एसबीआई फिर भी होशियारी दिखा रही है। अदालत ने बैंक से पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया। बैंक ने अल्फा न्यूमिरिक नंबर क्यों नहीं बताया। अदालत ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। अदालत का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है। अदालत ने कहा कि बॉन्ड खरीदने और भुनाने की तारीख बतानी चाहिए थी। दरअसल यूनिक आईडी हर एक बॉन्ड का यूनिक नंबर होता है। इसके जरिए आसानी से यह पता लगाया जा सकेगा कि आखिर किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को चंदा दिया है। चंदा देने वाले और चंदा पाने वालों की सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बॉन्ड नंबरों से पता चल सकेगा कि किस दानदाता ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम शुरू से ही विवादों में घिरी रही है। इस स्कीम के तहत जनवरी 2018 और जनवरी 2024 के बीच 16518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और इसमें से ज्यादातर राशि राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के तौर पर दी गई थी। इस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिला था।

इन बॉन्ड्स पर पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठ रहे थे और ये आरोप लग रहा था कि ये योजना मनी लॉन्डरिंग या काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैधता पर सवाल उठाते हुए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स (एडीआर), कॉमन कॉज और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत पांच याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एडीआर के संस्थापक और ट्रस्टी प्रोफेसर जगदीप छोकर ने कहा कि यह फैसला काबिले-तारीफ है। इसका असर यह होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम बंद हो जाएगी और जो कॉरपोरेट्स की तरफ से राजनीतिक दलों को पैसा दिया जाता था जिसके बारे में आम जनता को कुछ भी पता नहीं होता था, वो बंद हो जाएगा। इस मामले में जो पारदर्शिता इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम ने खत्म की थी वो वापस आ जाएगी। इस मामले से बतौर याचिकाकर्ता जुड़े रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं कि यह स्कीम असंवैधानिक थी और लेवल प्लेइंग फील्ड (समान अवसर) को खत्म करती थी। येचुरी ने कहा कि शुरू से ही उनकी और उनकी पार्टी की राय यह थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक भ्रष्टाचार को वैध बनाने का साधन है। सीताराम येचुरी कहते हैं कि सही तो यही होगा कि पैसा वापस किया जाए क्योंकि यह स्कीम ही असंवैधानिक है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिन कंपनियों ने यह पैसा राजनीतिक दलों को दान किया, यह उन्हें वापस न जाए। ये पैसा सरकारी खाते में जमा होना चाहिए और चुनावों के स्टेट फंडिंग की योजना को शुरू किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं उनकी अपेक्षा थी कि उचित होगा कि हमारे लिए भी एक गोपनीयता रखी जाए। उन्होंने कहा कि कोई सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो चंदा देने वालों के खिलाफ हो जाते हैं।

इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपना काम करें। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से चुनाव की फंडिंग पर बहुत कम फर्क पड़ता है क्योंकि चुनावी फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा नकदी में आता है। यह फैसला केवल फंडिंग की पारदर्शिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सत्तारूढ़ दल को धन मिलता रहेगा जबकि विपक्ष के धन का स्रोत कम हो जाएगा। न्यायालय ने बार-बार सरकार के साथ सीधे टकराव से दूर रहने का विकल्प चुना है, खासकर सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं या अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर। चूंकि य फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है तो यह बताता है कि न्यायाधीशों ने दृढ़ता से महसूस किया कि बॉन्ड योजना संवैधानिक रूप से अस्थिर थी। सीबीआई की तरह एसबीआई की चुनावी फंड के मामले में हुई किरकिरी से साबित हो गया है कि पिंजरे का तोता सिर्फ एक ही विभाग नहीं है। सरकारी विभाग सत्तारूढ़ दलों की कठपुतलियों की तरह काम करते हैं। सत्ता बदलते ही दूसरे दलों की भाषा बोलने लगते हैं। दरअसल जब तक कामकाज और पारदर्शिता को लेकर कानूनी तौर पर सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक अदालतों के आदेशों की मार नौकरशाही पर पड़ती रहेगी।

संपादक की कलम से

एक देश, कई चुनाव

भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 'एक देश, एक चुनाव' पर अपनी रपट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। यह रपट व्यापक विमर्श का महादस्तावेज है, लिहाजा यह संदेह करना कि देश में एक ही पार्टी काम करेगी या 2029 के बाद देश में चुनाव ही नहीं होंगे, फिजूल और पूर्वाग्रह है। करीब 7 माह के दौरान 65 बैठकें की गईं, 11 रपटों का अध्ययन किया गया और 21,558 लोगों से बातचीत कर उनकी राय ली गई। उनमें से 80 फीसदी से अधिक लोग 'एक देश, एक चुनाव' के समर्थन में थे। विशालकाय रपट 18,626 पन्नों की है। गौरतलब यह है कि देश के चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशों- जस्टिस दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद अरविंद और यूयू ललित- ने 'एक चुनाव' का समर्थन किया है। उच्च न्यायालय के 12 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से सिर्फ तीन ही विरोध में थे। जाहिर है कि कानून और संविधान के विशेषज्ञों का प्रचंड बहुमत 'एक चुनाव' के पक्ष में है। समिति ने 47 राजनीतिक दलों का पक्ष भी जाना, तो 15 दलों ने विरोध जताया। उनमें कांग्रेस, सीपीएम, बसपा, आप सरीखे राष्ट्रीय दलों समेत तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सीपीआई, ओवैसी की पार्टी, एमडीएमके, नगा पीपुल्स फ्रंट, सीपीआई (एमएल) और सपा आदि क्षेत्रीय दल भी नई व्यवस्था के खिलाफ हैं। जाहिर है कि वे मौजूदा सत्ता-पक्ष भाजपा-एनडीए के विरोधी हैं, लेकिन क्या 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के समर्थन को खारिज किया जा सकता है? याद रहे कि कांग्रेस ही उस समय देश पर राज कर रही थी, जब 'एक चुनाव' ही होते थे।

लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। यह दीगर है कि तब संसाधन कम चाहिए थे और मतदान मतपत्रों के जरिए होते थे। अब मौजूदा आम चुनाव में ही 10 लाख से अधिक ईवीएम लगाई जाती हैं और 1.5 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी चुनाव ड्यूटी देते हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती इनसे अलग है। जाहिर है कि 'एक चुनाव' की स्थिति में ईवीएम ही 40 लाख के करीब चाहिए और सिर्फ दो कंपनियां ही देश में ईवीएम बनाती हैं। उनका उत्पादन औसत भी 4 लाख सालाना से कम है। चूंकि नई व्यवस्था 2029 के आम चुनाव से लागू करने की बात कही जा रही है, लिहाजा यह इतनी सहज और आसान व्यवस्था नहीं होगी कि देश में 'एक चुनाव' ही होने लगें। सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तो यह है कि 'एक चुनाव' को शुरू करने के लिए संविधान में 18 संशोधन करने होंगे। संसद में कोई भी संविधान-संशोधन दो-तिहाई बहुमत, यानी 362 सांसदों के समर्थन, से ही संभव हो सकता है। हालांकि कुछ संशोधनों के लिए 50 फीसदी राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार चुनाव आयोग को है।

इसके लिए अनुच्छेद 325 में बदलाव करना होगा। अनुच्छेद 324-ए में बदलाव करते हुए निगमों और पंचायतों के चुनाव भी आम चुनाव के साथ कराए जाएंगे। अनुच्छेद 368-ए के तहत ऐसे संविधान संशोधन बिल को 50 फीसदी राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी। इसी तरह विधानसभा वाले संघशासित क्षेत्रों के लिए अलग से संविधान संशोधन बिल पारित कराने होंगे। दरअसल देश की आजादी के बाद पहला आम चुनाव 1952 में कराया गया। उसके बाद 1957, 1962 और 1967 तक 'एक चुनाव' की ही व्यवस्था थी, लेकिन 1968, 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई, लिहाजा 'एक चुनाव' की परंपरा ही टूट गई। अब नए सिरे से वही व्यवस्था लागू करना पेचीदा मामला है, क्योंकि विधानसभाओं के कार्यकाल भिन्न हैं।

चर्चा

अदालती दरवाजे पर ये आंसू

आय प्रमाणपत्र की जरूरत पर आम आदमी के अधिकार अगर अदालत के दरपेश सरकारी कार्यसंस्कृति का निकम्मापन साबित हो सकते हैं, तो जनता की व्यथा का अंदाजा लगाया जा सकता है। माननीय हाई कोर्ट ने आनी के तहसीलदार की कार्यशैली पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था के कर्ताधर्ताओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हैरानी यह कि तमाम गारंटियों, सुशासन के वादों और नित नए प्रयोगों के बावजूद ढर्रा वहीं का वहीं टिका है। एक महिला के आय प्रमाणपत्र के सत्यापन को मिलीं प्रशासनिक ठोकरें, यह लिहाज भी न कर पाईं कि इससे कार्यसंस्कृति, व्यवस्था व सरकार की बदनामी होगी और एक अधिकारी ने एडीएम कोर्ट के आदेश को कारपेट के नीचे छुपा दिया। जो कार्य 22 दिसंबर 2022 को निचले स्तर पर सामान्य प्रक्रिया में हो जाना चाहिए था, उसे सवा साल बाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर हल करने का न्याय मिल रहा है। यहां वाजिब सवाल यही है कि प्रशासनिक प्रक्रिया के कायदे-कानूनों में इतनी शिथिलता आ गई है कि आम नागरिक को अदालती प्रक्रिया के उच्च स्तर ढूंढने पड़ेंगे। अगर इसी माथा रगड़ाई के चरित्र में हिमाचल का शासन-प्रशासन चलता रहा, तो अदालतों के दरवाजे पर समाज की जरूरतें आंसुओं से भीगी दिखाई देंगी। जाहिर तौर पर अदालत की टिप्पणी पर गौर फरमाते हुए प्रदेश सरकार को प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से हर दफ्तर को संवेदनशील, कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सुधारों व नियमों की नई परिपाटी स्थापित करनी होगी। बेशक पिछली सरकार ने जनमंचों की अंतहीन श्रृंखला खड़ी कर दी या मौजूदा सरकार ने 'सरकार गांव के द्वार' का अखंड पाठ शुरू कर दिया, लेकिन आनी प्रशासन के कान में अगर जूं तक नहीं रेंगी, तो ऐसे प्रपंचों की क्या आवश्यकता। अगर सरकार अदालतों में फंसे मामलों में आम नागरिक के अनुभवों का संज्ञान ले तो मालूम हो जाएगा कि व्यवस्था के सुराखों से कितना दर्द बह रहा है। आश्चर्य यह कि जो राज्य अपने चुनावी वादों से सत्ता के इरादों तक सिर्फ कर्मचारियों के हितों की बात करता है, उसके प्रशासनिक बिछौने पर इतने कांटे छिपे हैं। कमोबेश यही हाल सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय निकायों तथा विकास के कार्यों का भी है। हम दरअसल सियासी वर्चस्व में प्रशासनिक कामकाज और व्यवस्था का परचम देख रहे हैं और सत्ता की अदलाबदली में स्थानांतरण के हथियार से कर्मचारियों व अधिकारियों को सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। हम एक ही पोशाक में राजनीति और प्रशासन को अनुशासित व सक्षम नहीं बना सकते। अभी हाल ही में जिन नौ विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया, उनके विधानसभा हलकों के अधिकारियों-कर्मचारियों को बदलने का कारण यही हो सकता है कि प्रशासन अब नेताओं की मिलकीयत की तरह चलता है। इसलिए कई बार फरियादी को नागरिक न मानकर उसे सियासी अखाड़े में देखकर काम होता है। इसका एक और उदाहरण नगर निगम धर्मशाला की महापौर का स्मार्ट सिटी प्रशासन के टकराव में देखा जा सकता है। कायदे से स्मार्ट सिटी के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का एक राष्ट्रीय स्वरूप, मानदंड व मानिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक अखाड़ेबाजी में नगर निगम के पार्षद या मेयर को अपनी मिलकीयत के तहत स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का रुतबा चाहिए।

डा. राजन तनवर

सगुण भक्ति का सूत्रधार : राम काव्य

तुलसी ने राम को किसी एक धर्म का बना कर स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने तो राम के व्यक्तित्व से समग्र संसार के जनमानस को पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने का आधार बनाकर प्रेरणा लेने का संदेश दिया। सगुण भक्ति का सूत्रधार राम काव्य ही है'

वेदों और पुराणों में वर्णित राजा दशरथ के पुत्र राम कालांतर में ईश्वरीय रूप में स्वीकार करके पूजे जाने लगते हैं। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण इस मान्यता को अधिक प्रबल एवं प्रगाढ़ करती है। आश्रम से निकलकर तमसा नदी के तट पर विचरण करते हुए वाल्मीकि ने एक व्याध द्वारा काम-मोहित क्रौंच-दंपति में से एक को अपना लक्ष्य बनाने पर क्रौंची के करुण क्रंदन को सुना तो उनका कवि हृदय चीत्कार कर उठा और कवि के हृदय का शोक निम्न श्लोक बनाकर फुट निकला-'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगण : शाश्वतीः समाः।/यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम्।।' व्याध को श्राप देकर महर्षि अपने आश्रम में लौट आए, किंतु उनका मन अशांत था। इसी समय ब्रह्माजी ने महर्षि के पास आकर कहा- 'ऋषे प्रबुद्धोऽसि रामचरितं ब्रूहि।' आपके प्रतिभा-चक्षु उन्मीलित हो गए हैं। अब आप नदियों में गंगा के समान सभी राजाओं में सर्वोच्च आदर्श श्रीराम के जीवन का वर्णन करें, जिससे लोक में आदर्श और मर्यादा की स्थापना हो सके। ब्रह्माजी ने श्री राम को विग्रहवान (शरीरधारी) धर्म घोषित किया था। ब्रह्मा जी के कथन को शिरोधार्य कर महर्षि ने रामायण की रचना की। इस ग्रंथ को आदि काव्य और इसके रचयिता को आदि कवि का गौरव प्राप्त हुआ। महर्षि के मुख से व्याध के लिए निकले श्लोक में जिस छंद का प्रयोग हुआ था तथा अपनी रचना में कवि ने जिन अन्य छंदों का प्रयोग किया, उन्हें भी वैदिक छंदों से भिन्न, सर्वथा नयी आविष्कृति कहा गया। पन्द्रहवीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के आरंभ होने से सभी भारतीय आर्य भाषाओं से लेकर स्थानीय बोलियों में भी राम भक्ति का नया रूप सामने आया।

यद्यपि इसका सूत्रधार दक्षिण के आलवर संतों को माना जाता है, तथापि यह स्वीकार किया जाता है कि आलवर संतों के माध्यम से ही राम भक्ति काव्य आंदोलन उत्तरी भारत में पहुंचकर जन-जन की राम के प्रति ईश्वरीय भावना को सुदृढ़ करने का आधार बना। 'हिंदी के साथ-साथ अन्य सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन प्रसंगों को लेकर विविध काव्यों की पुष्कल रचना हुई है। बंगला भाषा में कृतिवासी- कृत 'रामायण', तमिल में महाकवि कम्ब की 'कम्ब रामायण' तथा तेलुगू की 'रंग रामायण' एवं 'भास्कर रामायण' ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त सीमा तक हिंदी राम काव्य परंपरा को भी प्रभावित किया है। कृतिवासी- रामायण, वाल्मीकि रामायण के गौडिया पाठ से तथा 'कम्ब रामायण', 'रंग रामायण' एवं 'भास्कर रामायण' उसके दक्षिणात्य पाठ से उपकृत है। कृतिवासी रामायण पर समसामयिक शैव एवं शाक्त संप्रदायों का प्रभाव भी लक्षित किया जा सकता है। मराठी के सुप्रसिद्ध संत एकनाथ द्वारा प्रणीत भावार्थ रामायण ने भी परवर्ती भक्त कवियों को व्यापक प्रेरणा प्रदान की है। स्वामी रामदास की शिष्या वेणा बाई देशपांडे द्वारा रचित रामायण तथा स्वामी रामदास के ही एक अन्य शिष्य गिरिधर स्वामी की अद्भुत रामायण, मंगल रामायण, सुंदर रामायण, संकेत रामायण आदि लगभग छह रामायण से भी मराठी साहित्य की श्रीवृद्धि हुई है। असमिया में राम काव्य की शैली की दृष्टि से पद- रामायण, गीति-रामायण, कथा-रामायण, कीर्तनिया रामायण आदि विभिन्न रूपों में उपलब्ध होता है और राम काव्य के प्रणेताओं में माधव कन्दली, शंकर देव, माधव देव, अनंत कन्दली, रघुनाथ महंत, अनन्त ठाकुर, प्रभृति भक्त कवि अत्यधिक सुप्रसिद्ध हैं। गुजराती में यद्यपि राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य का प्रणयन अधिक हुआ है, किंतु राम काव्य की अविरल धारा इस भाषा में भी विद्यमान है और कवि भालण, विष्णुदास, मधुसूदन, श्रीधर आदि गुजराती राम काव्य के उल्लेख्य प्रणेता हैं।

उक्त भावना को प्रबल रूप में स्थापित करने के लिए राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख आधार स्तंभ कवि तुलसीदास हैं जिन्होंने जन भाषा अवधी में रामचरितमानस की रचना करके राम को जन-जन का प्रिय बना दिया। अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करने का विरोध तुलसीदास को तत्कालीन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का संचालन करने वाले विद्वानों का मुकाबला करते हुए झेलना पड़ा। अवधी में रामचरितमानस की रचना होने से उन्हें अपनी आजीविका पर आघात लगता हुआ प्रतीत हो रहा था। वे महसूस कर रहे थे कि यदि राम का आदर्शवादी एवं मर्यादा पुरुषोत्तम रूप आम जन अवधी भाषा के माध्यम से जान लेगा तो उनकी विद्वता की कदर कम होने लगेगी। इससे पूर्व उनके पूर्वज बौद्ध दर्शन एवं विचारधारा का विरोध कर चुके थे। सिद्धार्थ भारत में जन्म लेते हैं, अपनी तपस्या से बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। उस सुधारवादी विचारधारा को ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने भारत में पनपने नहीं दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म संसार के अन्य देशों में फलता-फूलता विकसित होता हुआ चला गया, किंतु भारतवर्ष में उसे वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका जो होना चाहिए था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं चाहती थी कि उनकी विचारधारा के अतिरिक्त कोई और धार्मिक विचारधारा इस देश में विकसित हो तथा जन-जन की पूजा का आधार बने। कलि काल में तुलसी से बढक़र राम भक्त कोई नहीं हो पाया है।

तुलसी ने राम के आदर्शवादी एवं मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को जन-जन तक पहुंचा कर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की जो मिसाल स्थापित की, उसका परिणाम यह हुआ कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का संसार की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। रामचरितमानस को बाइबल के समकक्ष रचना माना जाने लगा। तुलसी ने राम को किसी एक धर्म का बना कर स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने तो राम के व्यक्तित्व से समग्र संसार के जनमानस को पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने का आधार बनाकर प्रेरणा लेने का संदेश दिया। तुलसी का मानवता के लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। राम भक्ति काव्य मूलतः लोक धर्म और भक्ति-साधना का ही काव्य है। लोक पक्ष का यहां त्याग नहीं है। सगुण भक्ति का सूत्रधार राम काव्य ही है।

मैं निठल्ला नहीं बैठा हूं

देखिए जनाब! मुझ पर आप लाख तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन यह आरोप बिल्कुल नहीं लगा सकते कि मैं कुछ कर्ता-धर्ता नहीं हूं और निठल्ला बैठा सरकार की सब्सिडी खाता रहता हूं। ऐसा आरोप मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता। पचास-साठ लोग एक साथ मिलकर कहें तो भी नहीं सुन सकता। पहली बात तो यह है कि मेरे सारे खाते सील हैं। उनमें सब्सिडी आ ही नहीं सकती। दूसरा, मेरे पास सब्सिडी खाने की फुर्सत ही नहीं है। मैं दिन-रात व्यस्त ही बहुत रहता हूं और ऊपर से आप यह तोहमत लगा रहे हैं कि मैं निठल्ले बैठा रहता हूं। ऐसा भला हो भी कैसे सकता है? जिस तरह देश आजाद होने के बाद से लीडर लोग निठल्ले नहीं बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार निठल्ले नहीं बैठे हैं, कबूतरबाज निठल्ले नहीं बैठे हैं, जमाखोर निठल्ले नहीं बैठे हैं, कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, उसी तरह मैं भी निठल्ले थोड़ी बैठा हूं। कोई शक है तो मेरी आउटपुट देख लो। जब से इस दुनिया में आया हूं, कुछ न कुछ कर ही रहा हूं। चाहो तो थानों का रिकॉर्ड चेक कर लो। विजिलेंस वालों से पूछ लो। गुंडों, बाहुबलियों से पुष्टि करवा लो। छत्तीस सौ मामले मेरे खिलाफ चल रहे हैं। पचासों एफआईआर दर्ज हैं। दर्जनों घोटाले किए हैं। छेडख़ानी के मामले अलग से हैं। यहां तक कि सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने में भी कहीं कोई कसर बाकी नहीं रखी। आम आदमी से पूछ कर देख लो। वह ही आपको बता देगा कि हमने डंके की चोट पर फलां फलां की जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं और फलां फलां को झूठे मामलों में अंदर करवा रखा है। इतने सारे काम निठल्ले बैठकर थोड़ी हो सकते हैं। कमाल है।

फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैं निठल्ला बैठा हूं। कुछ कर नहीं रहा। क्या जो मैंने अब तक किया, वह किसी काम की श्रेणी में नहीं आता? क्या निठल्ला आदमी इतने काम कर सकता है? क्या पुलिस और लीडरों से सेटिंग निठल्ले बैठे हो जाती है! अगर पुलिस और लीडरों को कोई काम नहीं है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि मुझे भी कोई काम नहीं है! अपनी फैक्टरी में जो नकली खाद तैयार करता हूं, क्या वह कोई काम नहीं है? अपने बेटे के नाम पर चली दूसरी फैक्टरी में जो नकली दवाई तैयार करता हूं, तो क्या वह कोई काम नहीं है? क्या दोनों फैक्टरियां ऐसे ही चल रही हैं? अगर मैं निठल्ला होता तो घर में इतने नौकर चाकर कहां से होते? पत्नी की उंगलियों में इतनी रत्नजड़ित अंगूठियां कहां से आती! बाहुबली मेरे अंग संग क्यों रहते? उनके खर्चे मैं कहां से पूरे करता! विदेशी बैंकों में मेरे लॉकर कहां से होते? होटलों और क्लबों में जाकर इंजॉय कैसे करता? देसी और विदेशी सुंदरियां मेरी संगत क्यों करती? अधिकारी लोग मेरे घर में महंगे महंगे गिफ्ट लेकर क्यों आते! इतने सारे काम मैंने शुरू कर रखे हैं कि मैं निठल्ला बैठ ही नहीं सकता। अगर बैठ गया तो विरोधी कल को मेरे यहां रेड करवा देंगे। मुझे ऐसी असंवैधानिक चीजों से बहुत डर लगता है। मैं इनसे बचने की योजनाएं हर वक्त बनाता रहता हूं। निठल्ला तो बिल्कुल नहीं बैठता। लेकिन मेरे पास तो गप्पें मारने की भी फुर्सत नहीं है। इतने लोग सलाह लेने आते हैं कि कोरी गप्प मार कर अपना कीमती समय बर्बाद करने का टाइम ही नहीं मिलता। इतना बिजी हूं कि मुझे तो भगवान का नाम लेने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह उठते ही भगवान से क्षमा याचना करके कह देता हूं कि मेरी व्यस्तताओं को समझें और फिजूल में बुरा न मानें। भगवान को भी मालूम है कि मैं कभी निठल्ला नहीं बैठता। देश हित में कुछ न कुछ करके अपना हित साधता ही रहता हूं। कोई और काम न हो तो समाज सेवा कर लेता हूं। क्या समाज सेवा निठल्ले आदमियों के बस की बात है? फिर भी आपको शक है तो एक बात बताओ। अगर मैं निठल्ला बैठा हूं तो आपकी जड़ों में म_ा कौन डाल रहा है?

गुरमीत बेदी

फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैं निठल्ला बैठा हूं। कुछ कर नहीं रहा। क्या जो मैंने अब तक किया, वह किसी काम की श्रेणी में नहीं आता? क्या निठल्ला आदमी इतने काम कर सकता है? क्या पुलिस और लीडरों से सेटिंग निठल्ले बैठे हो जाती है!

फिक्स्ड डिपॉजिट या सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, किसमें पैसा लगाने में रहेगी समझदारी?

वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले निवेश कर देना होगा। लेकिन कई लोग तय नहीं कर पाते कि निवेश कहां करें। इसमें खासकर सीनियर सिटीजन शामिल हैं जो जोखिम लेने से बचते हैं। वे चाहते हैं कि उनके निवेश पर टैक्स तो बचे निवेश की रकम भी सुरक्षित रहे। हम बता रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए कौन-सी स्कीम सही रहेगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अगर आपको मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2023-24 में टैक्स बचाना है, तो 31 मार्च से पहले निवेश कर देना होगा। लेकिन, असल मुश्किल यह होती है कि निवेश करें कहां? यह सवाल इसलिए भी जायज होता है, क्योंकि हर किसी के लिए निवेश का इकलौता मकसद टैक्स बचाना ही नहीं हो सकता। उनके लिए ब्याज दर और लॉक-इन पीरियड जैसी चीजें भी अहमियत रखती हैं।

यह सवाल खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक जटिल हो जाता है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव वे अमूमन जोखिम लेने से बचते हैं। वह टैक्स बचाने के साथ अपना निवेश भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसे में वे टैक्स बचाने वाली FD (Fixed deposit) या सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) का रुख करते हैं।

आइए जानते हैं कि टैक्स बचाने, रिटर्न और लॉक-इन पीरियड के लिहाज से इन दोनों में बेहतर स्कीम कौन-सी है।

FD में क्या फायदा है?

बुजुर्ग निवेशक अमूमन फिक्स्ड डिपॉजिट को अधिक तरजीह देते हैं। एक तो इसमें पैसे सुरक्षित रहते हैं, दूसरे रिटर्न भी निश्चित रहता है। साथ ही टैक्स सेविंग भी हो भी जाती है। अगर आप एक, दो या फिर तीन साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो एफडी आपके लिए बेस्ट रहेगा।

पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए एफडी अकाउंट खोलने पर सालाना 6.9 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अगर आप तीन साल के लिए निवेश करते हैं, तो ब्याज दर 6.9 फीसदी हो जाएगी। वहीं, 5 साल की एफडी पर सबसे अधिक ब्याज मिलेगा, सालाना 7.7 फीसदी। इसमें ब्याज तो सालाना आधार पर मिलता है, लेकिन कैलकुलेशन तिमाही आधार पर होता है। इसमें न्यूनतम निवेश की सीमा 1000 है, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं। आपके पास जितना पैसा है, एफडी करा सकते हैं।

5 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश की गई राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट का फायदा मिलता है।

SCSS में निवेश क्यों करें?

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) फिलहाल सरकार की उन चुनिंदा छोटी बचत योजनाओं में शुमार है, जिन पर 8.2 फीसदी जैसा भारी-भरकम ब्याज मिलता है। इसमें आपको 1 हजार से 30 लाख रुपये तक इन्वेस्ट करने की इजाजत होती है। आप एक से ज्यादा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन निवेश की कुल रकम 30 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती।

इसमें निवेश पांच साल बाद मैच्योर होता है। इसे तीन साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने स्कीम में 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का निवेश किया है, तो कुल 14.28 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें 80C के तहत 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट भी मिलती है।

FD अच्छी है या SCSS?

इसका जवाब आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आप कम समय का लॉक इन पीरियड चाहते हैं, तो एफडी का रुख कर सकते हैं। लेकिन, इससे ज्यादा समय के लिए निवेश करना है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम को ज्यादा बेहतर विकल्प कहा जा सकता है।

FPI को फिर लुभा रहा भारत का बाजार, इक्विटी और डेट मार्केट्स में जमकर कर रहे हैं निवेश

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) मार्च में फिर भारत के इक्विटी और डेट बाजारों की आकर्षित हुए और बड़े पैमाने पर निवेश किया। वे 15 मार्च तक FPI इक्विटी बाजारों में 40710 करोड़ रुपये और डेट बाजारों में 10383 करोड़ रुपये लगा चुके हैं। जानकारों का कहना है कि जनवरी में बड़ी बिकवाली करने वाले विदेशी निवेशक फरवरी में शुद्ध खरीदार रहे लेकिन निवेश की मात्रा कम रही थी।

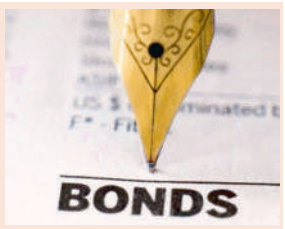

नईदिल्ली: मार्च में एक बार फिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) घरेलू इक्विटी और डेट बाजारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। डिपॉजिटरी के डेटा के अनुसार, 15 मार्च तक FPI इक्विटी बाजारों में 40,710 करोड़ रुपये और डेट बाजारों में 10,383 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक FPI इक्विटी में 16,505 करोड़ और डेट में 52,639 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं।

जानकारों का कहना है कि जनवरी में बड़ी बिकवाली करने वाले विदेशी निवेशक फरवरी में शुद्ध खरीदार रहे, लेकिन निवेश की मात्रा कम रही थी। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार का कहना है कि मार्च में नई FPI ने बड़े पैमाने पर खरीदारी की है। हालांकि, इसमें थोक सौदों की संख्या ज्यादा रही है।

विजयकुमार का कहना है कि यह FPI गतिविधियों का वास्तविक संकेत नहीं हैं, लेकिन यह रुख आगे भी जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि अब FPI निवेशक अमेरिकी बांड यील्ड के अनुसार अपनी रणनीति बदल रहे हैं। अगर महंगाई में वृद्धि से आने वाले समय में अमेरिकी बॉन्ड पर यील्ड बढ़ता है तो FPI भारतीय बाजारों से निकासी कर सकते हैं।

हालांकि, पिछली बार अमेरिकी बॉन्ड पर अधिक यील्ड मिलने के बावजूद FPI ने भारतीय बाजार को ही तरजीह दी थी। इसकी वजह भारत की बेहतर आर्थिक संभावनाओं को माना गया था।

इक्विटी बाजारों में मार्च में मिड और स्मॉल कैप में कमजोरी दिखी है, जबकि लार्ज कैप में लचीलापन बना हुआ है। इस कारण FPI ने लार्ज कैप से बिकवाली घटा दी है। वे फिलाहल बैंकिंग, दूरसंचार और आटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्रों में सीमित दायरे में खरीदारी कर रहे हैं।

एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमैन क्या है, इससे आसान कैसे हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जानें पूरी डिटेल्स

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय कई लोगों को अपनी पिछली डिटेल याद नहीं रहती। इससे उन्हें ITR फाइल करने में दिक्कत होती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट Annual Information Statement लाया था। इसमें आपके पैन आधार और पते के साथ रिफंड जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। साथ ही अगर डिपार्टमेंट ने आपसे कोई जानकारी मांगी है तो उसका भी रिकॉर्ड होता है।

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना कई लोगों को पेचीदा काम लगता है। इसकी बड़ी वजह है कि उन्हें टैक्स से जुड़े नियम-कानून और दस्तावेजों की ज्यादा जानकारी नहीं होती। साथ ही, वे अपनी टैक्स फाइल (Income Tax Declaration) से जुड़ी डिटेल भी भूल जाते हैं।

लेकिन, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement-AIS) के बारे में पता है, तो आपकी कई मुश्किलें आसान हो सकती हैं।

इस सुविधा को नवंबर 2021 के पेश किया गया था। यह टैक्सपेयर्स की उन जानकारियों के बारे में बताता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहले से होती हैं। आइए AIS के बारे में सबकुछ विस्तार से जानते हैं।

क्या होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट?

इस स्टेटमेंट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जरूरी सभी जानकारियां भी शामिल होती हैं। इस फॉर्म में टैक्सपेयर्स की जानकारियां दो हिस्सों में होती हैं।

पार्ट A : इस हिस्से में करदाता की सामान्य जानकारियां होती हैं। जैसे कि पैन, मास्क्ड आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, एड्रेस, नाम और जन्म की तारीख। अगर इंडिविजुअल की जगह कोई कंपनी है, तो जन्म की जगह उसकी स्थापना वाली तारीख की जानकारी होती है।

पार्ट B : इसमें आपके टैक्स से जुड़ी तकनीकी जानकारियां दिखती हैं।

SFT की जानकारी : यहां स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (SFT) करने वाली कंपनियों से मिली जानकारी होती है। इसमें कंपनियों से मिला डिविडेंड और सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल रहता है।

डिमांड और रिफंड : इस सेक्शन से आपको यह पता चल जाता है कि किसी वित्त वर्ष में आपको कितना रिफंड जारी हुआ और आपसे किन जानकारियों डिमांड हुई थी।

अन्य जानकारियां: इस हिस्से में अन्य स्रोतों से मिली इंफॉर्मेशन शामिल होती हैं। मसलन- सैलरी का एनेक्सचर II फॉर्म, रिफंड पर मिलने वाला इंटरेस्ट, विदेशी मुद्रा की खरीदारी।

एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) कैसे डाउनलोड करें:

- इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- PAN/आधार और पासवर्ड से ITR फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- डैशबोर्ड मेनू पर AIS ऑप्शन दिखेगा, वहां Proceed पर क्लिक करें।
- आप सीधे AIS पोर्टल (ais.insight.gov.in/complianceportal) पर पहुंच जाएंगे।
- डिटेल देखने के लिए AIS पर क्लिक करें।

आप इसे PDF या JSON फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

सरकार ने यहां पर 15 रुपये तक कम किए पेट्रोल-डीजल के दाम, वजह के साथ जानिए नया रेट

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप द्वीप समूह की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने लक्षद्वीप द्वीप में एंड्रोट और कल्पेनी द्वीप के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम में 15.3 रुपये प्रति लीटर कमी की है। कावारत्ती और मिनिकॉय के लिए यह कटौती 5.2 रुपये प्रति लीटर है। आइए जानते हैं कि इन द्वीपों पर पेट्रोल डीजल के दाम में इतनी बड़ी कटौती क्यों की गई है?

नई दिल्ली। पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के दाम में दो रुपये की कटौती के बाद केंद्र सरकार ने अब लक्षद्वीप द्वीप समूह की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने लक्षद्वीप द्वीप में एंड्रोट और कल्पेनी द्वीप के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम में 15.3 रुपये प्रति लीटर कमी की है। कावारत्ती और मिनिकॉय के लिए यह कटौती 5.2 रुपये प्रति लीटर है।

यह जानकारी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करके दी। मंत्रालय ने बताया कि कीमतों में कटौती से आज प्रभावी भी हो गई हैं।

कीमतों में क्यों हुई इतनी बड़ी कटौती?

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने बताया कि लक्षद्वीप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) चार द्वीपों- कवरत्ती, मिनिकॉय, एंड्रोट और कल्पेनी को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति करता है। इस सरकारी कंपनी के डिपो कवरत्ती और मिनिकॉय में हैं। इनमें सप्लाई केरल के कोच्चि वाले IOCL डिपो से होती है।

मंत्रालय का कहना है कि लक्षद्वीप द्वीपों के डिपो में पेट्रोल-डीजल पहुंचाने की लागत काफी अधिक थी और उस हिसाब से फायदा नहीं होता था। इसलिए पूंजीगत खर्च की वसूली के लिए तीन साल पहले पेट्रोल और डीजल पर 6.90 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त चार्ज लगाया गया। यह 10 फीसदी वैट समेत 7.60 रुपये हो गया। लेकिन, अब वसूली पूरी हो गई है, इसलिए इस चार्ज को हटा लिया गया है।

बिक्री के हिसाब से अलग-अलग था चार्ज

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के मुताबिक- सभी द्वीपों की कीमत को बराबर करने के लिए 7.60 रुपये प्रति लीटर के चार्ज को बिक्री की मात्रा के आधार पर चार द्वीपों में बांटा गया था। इस वजह से मुख्य द्वीपों- कावारत्ती और मिनिकॉय में पेट्रोल और डीजल की रिटेल सेलिंग प्राइस में 5.2 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी। अन्य द्वीपों यानी एंड्रोट और कालपेनी के लिए यह कटौती लगभग 15.3 रुपये/लीटर रहेगी।

अब कितना होगा पेट्रोल का दाम?

नई कटौती के बाद अब लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर पेट्रोल 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.71 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लक्ष्यद्वीप में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले ऐसे नेता है, जिन्होंने #Lakshadweep वासियों को अपना परिवार माना है।

सेबी ने बदले कई नियम, शेयर बेचना-खरीदना आसान हुआ, FPI और IPO लाने वाली कंपनियों को भी बड़ी राहत

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में व्यापार को आसान और बेहतर बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और IPO के जरिये धन जुटाने वाली कंपनियों से जुड़े नियम शामिल हैं। इन बदलावों से FPI और IPO लाने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। आइए इन बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

मुंबई: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शुक्रवार को हुई बोर्ड मीटिंग में व्यापार को आसान और बेहतर बनाने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिये धन जुटाने वाली कंपनियों से जुड़े नियम शामिल हैं।

बैठक में 25 कंपनियों के शेयरों के साथ ट्रेडिंग के दिन निपटान (टी+0) प्रणाली का बीटा संस्करण लांच करने को भी मंजूरी दी गई। सेबी ने कहा कि बीटा वर्जन के यूजर्स समेत सभी के हित और परामर्श को ध्यान में रखेगा। T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन (T+0 Beta Version) लॉन्च होने के बाद निवेशकों और ट्रेडर्स को शेयर बेचते ही पूरी रकम मिल जाएगी।

सेबी ने बताया कि बोर्ड बैठक में आईपीओ या राइट्स इश्यू लाने के लिए जमा की जाने वाली एक प्रतिशत सुरक्षा राशि की जरूरत को खत्म करने का फैसला लिया गया है। साथ ही अप्रत्याशित घटना के चलते ऑफर समापन की तिथि को आगे बढ़ाने की छूट दी गई है। इससे आईपीओ लाने वाली कंपनियों को लाभ होगा।

बोर्ड ने एफपीआई की ओर से भौतिक जानकारी देने की समय-सीमा में भी ढील को भी मंजूरी दी है। अभी एफपीआई को अपने डीडीपी को पहले से दी गई जानकारियों में किसी बड़े बदलाव का खुला 7 वर्किंग डेज के भीतर करना होता है। लेकिन, अब FPI के किसी बदलाव के बारे में बताने और उससे जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए 30 दिन की मोहलत होगी।

सेबी ने कहा कि नए उपायों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी और उसी के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।

दो महीने में 40 अरब डॉलर घटी एलन मस्क की दौलत, जानें रईसों की लिस्ट में पहले से तीसरे नंबर पर कैसे खिसके टेस्ला के मालिक

टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क की दौलत 2024 के शुरुआती करीब ढाई महीनों में 40 अरब डॉलर घट गई है। वह सबसे रईसों की लिस्ट में भी तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। टॉप 10 में से किसी और भी अरबपति की दौलत इतनी तेजी से नहीं घटी है। मस्क की नेट वर्थ घटने की क्या वजह है? इस लिस्ट में अडाणी और अंबानी कहां हैं? आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलन मस्क (Elon Musk) अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। लेकिन, इस बार वह अपने बिजनेस में डाउनफॉल के चलते सुर्खियों में हैं।

इस साल यानी 2024 के शुरुआती करीब ढाई महीने में ही उनकी दौलत में 40 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट आ चुकी है। अगर टॉप 10 रईसों की लिस्ट देखें, तो इस दौरान बाकी किसी की संपत्ति इतनी तेजी से नहीं घटी।

यही वजह है कि जिस मस्क के सिर पर कभी दुनिया के सबसे रईस शख्स का ताज था, वह आज इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स (Bloomberg Billionaire Index) के मुताबिक, शनिवार को मस्क की नेट वर्थ 189 अरब डॉलर थी।

रईसों की लिस्ट में अब टॉप पर कौन?

फिलहाल फ्रांसीसी लग्जरी फैशन कंपनी Louis Vuitton के फाउंडर बर्नार्ड अरनॉल्ट (Bernard Arnault) दुनिया के सबसे रईस शख्स हैं। उनकी नेट वर्थ 201 अरब डॉलर हैं। वहीं, ईकॉमर्स कंपनी अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस (Amazon founder Jeff Bezos) इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, 198 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ। बेजोस इस हफ्ते की शुरुआत में मस्क को पीछे छोड़कर सबसे रईस बने थे, लेकिन अब अरनॉल्ट उनसे भी आगे निकल गए हैं।

अमीरों की लिस्ट में क्यों फिसले मस्क?

मस्क की रईसी का आधार है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार मेकर टेस्ला (Tesla)। इसमें मस्क की हिस्सेदारी 21 फीसदी है। लेकिन, पिछले कुछ समय से टेस्ला के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। इस साल अब तक कंपनी की नेट वैल्यू 29 फीसदी तक घट चुकी है। टेस्ला के लिए चीन बड़ा बाजार है। लेकिन, इस हफ्ते कंपनी ने बताया कि उसकी चीन बिक्री के आंकड़े काफी निराशाजनक रहे।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, 15 हजार निजी मुचलके पर मिली जमानत

परिहवन विशेष न्यूज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचकर अदालत में पेश हुए। अदालत ने उन्हें 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने रूटों से लेकर कोर्ट तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सुबह सात बजे ही सड़कों और कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दे दी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) ने दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर पेश न होने पर ईडी द्वारा दर्ज दो शिकायतों के मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी। अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए थे।

ACMM दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को जमानत दे दी। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 174 जमानती है और दोनों शिकायत मामलों में 15,000 हजार रुपये का बॉन्ड देने का निर्देश दिया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, जोहेब हुसैन और साइमन बेंजामिन ईडी की ओर से पेश हुए जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता, अधिवक्ता राजीव मोहन, मोहम्मद इरशाद, मुदित जैन और संप्रिक्ता घोषाल अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए।

केजरीवाल के वकील ने कही ये बात

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अदालत के सामने पेश हो गए हैं, ऐसे में कोई भी निर्णय आने तक केजरीवाल को जाने दिया जाए। अदालत ने सीएम को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके और एक लाख की सिक्योरिटी पर जमानत दी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने विभिन्न रूटों से लेकर कोर्ट तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। सुबह सात बजे ही सड़कों और कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे।

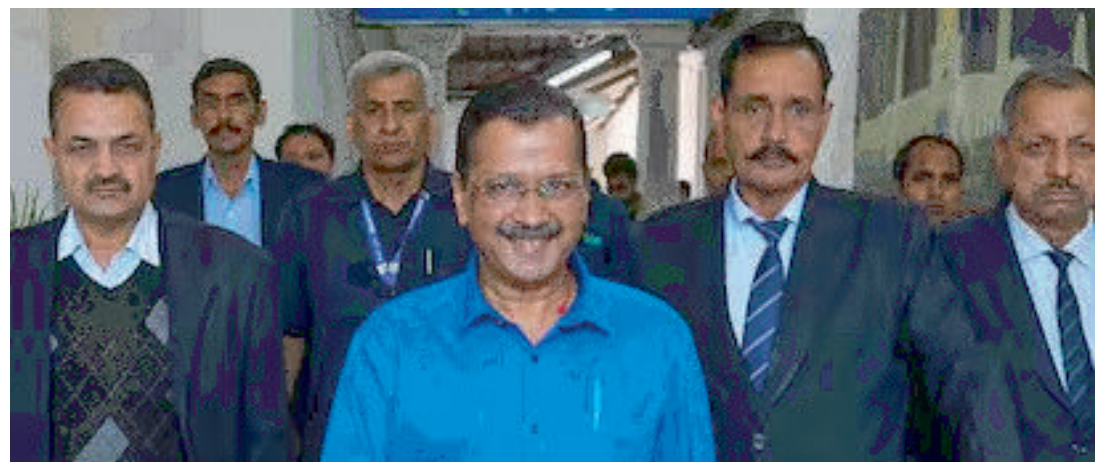

दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर की समस्या को लेकर दिए जांच के आदेश, आतिशी बोलीं- जवाबदेही तय की जाएगी

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बताया कि पानी और सीवर की समस्या पर अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बीते एक साल से इस समस्या के बनने के कारणों की जांच के भी आदेश दिए ताकि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड शहरी विकास विभाग और वित्त विभाग के बीच तालमेल न होने समस्या हो रही है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पानी और सीवर की समस्याओं पर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में शुक्रवार को सदन में मुख्य सचिव अधिकारियों समेत पेश हुए। उन्होंने दीर्घकालिक समाधान की रिपोर्ट भी जल मंत्री आतिशी को सौंप दी। आतिशी ने विधानसभा को बताया कि पानी और सीवर की समस्या पर अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बीते एक साल से इस समस्या के बनने के कारणों की जांच के भी आदेश दिए ताकि संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सके।

चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने अपने-अपने इलाके की समस्याओं को रखा और जल मंत्री आतिशी ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह में जलापूर्ति और सीवरेज को लेकर इतने काम हो सकते हैं तो पिछले छह माह से बंद क्यों थे?

दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए: आतिशी

उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से जल बोर्ड, शहरी विकास विभाग और वित्त विभाग के बीच तालमेल न होने का खामियाजा दिल्ली निवासी भुगत रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान सीवर ओवर फ्लो, दूषित जल, लीकेज संबंधित समस्याओं के तात्कालिक और दीर्घकालीन समाधान को लेकर संकल्प पत्र रखा गया, जिसे विधानसभा ने ध्वनि मत से पास किया।

अपर यमुना बोर्ड में भी इस मुद्दे को उठाया गया

आतिशी ने यह भी साझा किया कि दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकार हिमाचल प्रदेश से बात कर रही है और अपर यमुना बोर्ड में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में बहुत से इलाके ख़ासतौर पर यमुना के आसपास के इलाके और उत्तरी दिल्ली में भूजल का स्तर अच्छा है और पानी की गुणवत्ता भी ठीक हैं। ऐसे में सरकार द्वारा भूजल स्तर बढ़ाने का प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई है।

सदन में पेश संकल्प पत्र की मुख्य बातें:

1. मुख्य सचिव पानी और सीवर की समस्याओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान की निगरानी और पर्यवेक्षण करना जारी रखेंगे।

2. भूजल से जल संसाधनों की वृद्धि के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी।

3. टैंकर की कमी की शिकायतें भी सामने आ रही है, इसलिए पहले जितनी संख्या में पानी के टैंकरों को बहाल किया जाए। मुख्य सचिव क्षेत्रीय विधायकों से परामर्श के बाद ही टैंकरों की संख्या कम करे।

4. चूंकि दिल्ली के कई हिस्सों में बरसाती नाले के अभाव में सीवर ओवरफ्लो का सामना करना पड़ता है, इसलिए मुख्य सचिव इस समस्या के समाधान के लिए एमसीडी के साथ समन्वय करेंगे।

5. बरसाती नाले के मुद्दे का समाधान होने तक, दिल्ली भर में सीवर ओवरफ्लो को रोकने के लिए सीवर सफाई मशीनों की संख्या और कितनी आवृत्ति के साथ सीवर की सफाई और गाद निकालने की आवश्यकता है, इसका आकलन करने की आवश्यकता है।

6. सभी ट्रंक और परिधीय सीवरों से गाद निकालने का काम समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

7. एक्शन टेकन रिपोर्ट में निविदा प्रक्रिया में बताए गए कार्यों के अवार्ड किए जाने और समापन के संबंध में समय-सीमा प्रदान करने की आवश्यकता है।

8. मुख्य सचिव जल बोर्ड, शहरी विकास विभाग और वित्त के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करें, ताकि पानी और सीवरेज जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रभावित न हों।

9. मुख्य सचिव उपरोक्त सभी मुद्दों के साथ-साथ लंबित शिकायतों पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। 22 मार्च को सदन की बैठक में मुख्य सचिव इस पर एक रिपोर्ट देंगे।

दिल्ली में 3 स्तरों पर घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस, AAP के साथ कॉमन मिनिमम एजेंडा लाने पर विचार

कांग्रेस पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। आप चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को तीन सीटें मिली हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव भले ही राष्ट्रीय स्तर का हो लेकिन स्थानीय मुददों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसलिए कांग्रेस इस बार घोषणा पत्र को लेकर कुछ अलग फैसला लिया है।

नई दिल्ली। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस न केवल पहली बार राजधानी में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, बल्कि घोषणा पत्र भी तीन स्तरों पर जारी करने की तैयारी में है। एक घोषणा पत्र राष्ट्रीय स्तर पर जारी होगा, जिसमें दिल्ली के भी कुछ मुददे शामिल रहेंगे। एक दिल्ली के लिए अलग से बनाया जाएगा जो कांग्रेस के हिस्से में आई तीनों सीटों- उत्तर पूर्वी, चांदनी चौक और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लिए स्थानीय स्तर पर भी अलग घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।

दिल्ली के लिए अलग होगा घोषणा पत्र

वरिष्ठ पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव भले ही राष्ट्रीय स्तर का हो, लेकिन स्थानीय मुददों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसीलिए घोषणा पत्र अनेक स्तरों पर बनाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी घोषणा पत्र जारी करेगी। इसके लिए प्रदेश इकाई से भी ऐसे सभी सुझाव भेज दिए गए हैं, जिन्हें उसमें शामिल किया जा सकता है।

एक घोषणा पत्र पार्टी दिल्ली के लिए अलग से जारी करेगी। मतलब, यहां के ऐसे कौन से मुददे हैं, जिन्हें लेकर संसद में आवाज उठाई जा सकती है। ऐसे मुददो पर पार्टी की घोषणा पत्र समिति काम कर रही है। इसी तरह एक घोषणा पत्र पार्टी स्थानीय स्तर पर लाएंगे। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में कांग्रेस तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तीनों की भौगालिक स्थिति ही नहीं, समस्याएं और जरूरतें भी अलग हैं।

इंद्रप्रस्थ ढूंढ़ने के लिए एएसआई का अंतिम प्रयास, पुराना किला में फिर से होने जा रही खुदाई

दिल्ली में इंद्रप्रस्थ ढूंढने के लिए एक बार फिर पुराना किला में खोदाई होने जा रही है। यह एएसआई का अंतिम प्रयास होगा। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ पुराना किला के टीले पर थी या नहीं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) लगातार प्रयास करता रहा है। मगर स्पष्ट रूप से ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ ढूंढने के लिए इस बार अंतिम प्रयास के तहत खोदाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) उतरेगा। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ ढूंढने के लिए एक बार फिर पुराना किला में खोदाई होने जा रही है। देश की आजादी के बाद से छठी बार यह खोदाई होने जा रही है। एएसआई ने खोदाई के लिए अनुमति दे दी है।

अगले महीने शुरू हो सकती खुदाई

माना जा रहा है कि खोदाई अगले माह से शुरू हो सकती है। भारत सरकार के सुझाव के चलते इस बार खोदाई के लिए अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। नवीनतम तकनीक के तहत उत्खनन से पहले एएसआई लिडार सर्वेक्षण कराने की योजना बना रहा है। इसके माध्यम से जमीन के अंदर दबे अवशेषों के बारे में पता लगाया जाता है।

पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ पुराना किला के टीले पर थी या नहीं, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) लगातार प्रयास करता रहा है। आजादी के बाद से यह पांचवां प्रयास है, जब इस मामले से पर्दा उठाने के लिए खोदाई शुरू होगी। इस कार्य को फिर से एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी वसंत स्वर्णकार ने हाथ में लिया है।

पुराने किले में 3 बार हुई खुदाई

यह वह अधिकारी हैं जो पद्मविभूषण प्रो बी बी लाल के बाद तीन बार पुराना किला में खोदाई करा चुके हैं। पहले हो चुकी खोदाई में काफी कुछ मिला है, मगर स्पष्ट रूप से ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है, जिसके आधार पर सीधे तौर पर पुरातात्विक आधार पर यह दावा किया जा सके कि पुराना किला में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यही वह बेचैनी है जो एएसआई के अधिकारियों को परेशान कर रही है।

एएसआई को उम्मीद है कि यहां इंद्रप्रस्थ से संबंधित जरूर कोई न कोई ठोस प्रमाण मिलेगा। हालांकि, पांच बार की हुई खोदाई में यहां वे चित्रित मृदभांड मिले हैं, जिन्हें महाभारत के समय से जोड़ कर देखा जाता है। सोलहवीं शताब्दी में बने पुराने किले के नीचे परीक्षण के तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक प्रो. बीबी लाल द्वारा 1954-55 और 1969-1973 में खोदाई कराई गई थी। इसके ठीक 41 साल बाद एएसआइ ने 2013-14 और फिर 2017-2018 में और वहां 2022-23 में यहां खोदाई कराई। हर बार खोदाई में मिलते जुलते प्रमाण मिले हैं।

क्या क्या मिला खोदाई में

टेराकोटा के खिलौने मिले। बढ़िया भूरे रंग के चित्रित मिट्टी के मिले टुकड़ों से बर्तनों के बारे में पता चला, जिन पर सामान्यतः काले रंग में साधारण चित्रण किए गए थे। ये बर्तन पुरातत्व वेत्ताओं के बीच भूरे रंग के चित्रित बर्तनों के नाम से विख्यात हैं। प्रायः ईसा से 1000 वर्ष पूर्व के हैं। चूंकि ऐसे प्रमाण वाले बर्तन महाभारत की कहानी से संबद्ध अनेक स्थलों पर पहले भी पाये गए थे और इनका काल 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया था।

इनके यहां से प्राप्त होने से महाभारत के प्रसिद्व पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का पुराने किले के स्थल पर होने वाली परंपरा को बल मिला है। कहा जाता है कि पांडवों ने ईसा पूर्व 1400 वर्ष सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी इन्द्रप्रस्थ के रूप में बसाया था। 1955 में पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग में हुई पुरातात्विक खोदाई में कुछ मिट्टी के पात्रों के टुकड़े पाए गए जो कि महाभारतकालीन पुरा वस्तुओं से मेल खाते थे।

70 साल में दिल्ली में 24 बार खोदाई

पुराना किला-1954-55, 1969-70,71,72 से 73 तक, 2013 से 15 तक, 17-18 तथा 2022-23 तक।

मकदूम साहेब मास्क-1973-74

सीरी फोर्ट-1976-77

सीरी फोर्ट दीवार-2003-2003

लालकोट और किला राय पिथौड़ा-1957-58

लाल कोट-1958-60

लाल कोट और अनंगताल-1992 से 95 तक

सलीमगढ़ किला-2007-8

जादव भवन चन्द्रशेखरपुर में होगा

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : राज्य कैबिनेट की बैठक शनिवार को हुई । राज्य सरकार के पांचवें कार्यकाल की यह आखिरी कैबिनेट बैठक थी । मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है । चुनाव की तारीख की घोषणा और आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य कैबिनेट की यह आखिरी अहम बैठक थी ।जल संसाधन, वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री तुकुनी साहू, मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना, विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव अनु गर्ग, अपर मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू, मुख्य सचिव सुरेश कुमार बिश्केथ ने आज की कैबिनेट बैठक में सात विभिन्न विभागों के प्रस्ताव पारित किये ।14 प्रस्तावों एवं निर्णयों की जानकारी आज की कैबिनेट बैठक में मंत्री टुकुनी साहू ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पिछले 5 वर्षों में दिए गए राज्य के विकास की संभावनाओं पर प्रकाश किया।

हालांकि, कैबिनेट बैठक के फैसले के मुताबिक, जादव भवन चन्द्रशेखरपुर में होगा । काउंसिल का 5 करोड़ 60 लाख प्रीमियम माफ करने को कैबिनेट की मंजूरी। इसी तरह नदी पर एक और पुल बनाया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है । सालेपुर ब्लॉक ब्राह्मणखंड-साहुखेत मार्ग पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। पुल के निर्माण पर जहां 128 करोड़ रुपये खर्च होंगे, वहीं 3 साल में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है ।

होलाष्टक

होलाष्टक समय-:

होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 17 मार्च 2024, रविवार से शुरू होंगे और फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च 2024 पर समाप्त होंगे। इस दिन होलिका दहन होगा और 25 मार्च 2024 को रंगवाली होली खेली जाएगी।

होलाष्टक...?

होलाष्टक शब्द होली और अष्टक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है होली के आठ दिन। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता है।

मांगलिक कार्य वर्जित-:

होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं, धार्मिक मान्यता के अनुसार इन आठ दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह निर्माण, गृह प्रवेश आदि कार्य वर्जित माने जाते हैं।।

दिल्लीवासी भीषण गर्मी झेलने के लिए हो जाएं तैयार, अगले चार दिनों में बढ़ेगा तीन डिग्री तक तापमान

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में गर्मी की एंट्री हो गई है और राजधानीवासी इसके लिए अब तैयार हो जाएं। दरअसल मौसम विभाग ने कहा कि अगले तीन-चार दिन में अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना है। यहां तक कि मंगलवार तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि शुक्रवार को हवा की रफ्तार 25 किमी प्रति घंटे तक की रही।

नई दिल्ली। लगातार गर्म हो रहे मौसम में दिल्ली का तापमान अगले चार दिन में तीन डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आसमान साफ रहने एवं दिन भर तेज धूप के चलते गर्मी में बढ़ोतरी होगी।

दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कुछ दिन से तापमान व गर्मी दोनों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यह बात अलग है कि शुक्रवार को हवा की रफ्तार 25 किमी प्रति घंटे तक की रही। इसके चलते तापमान में एक दिन पहले की तुलना में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अगले तीन-चार दिन में अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना है। यहां तक कि मंगलवार तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है।

अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 28.7 डिग्री

शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 13.9 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 79 से 22 प्रतिशत तक रहा।

दिल्ली का एक्यआई 127 रहा

उधर, मौसम की मेहरबानी से दिल्ली की हवा लगातार साफ बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली का एक्यूआई 127 रहा। इस स्तर की हवा को 'मध्यम' श्रेणी में रखा जाता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023